● वर्ष-5

● अंक-228

रायपुर, मंगलवार
12 मई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8› जोन-3 में पहला जन समस्या...

सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, पोखरण का जिक्र कर बोले-

दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती

गिर सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। भगवान शिव को समर्पित और बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर, भारत की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत को प्रतिबिंबित करने वाले भव्य समारोहों का केंद्र था। यह महोत्सव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीपैड से वीर हमीरजी सर्कल तक एक रोड शो भी किया, जहां लगभग डेढ़ किलोमीटर के इस मार्ग पर हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए



जमा हुए। प्रधानमंत्री के गुजरते समय नागरिकों ने झंडे लहराए, नारे लगाए और उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत हैं, जो स्वयं काल स्वरुप हैं, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही क्रीड़ा है।

मोदी ने कहा कि दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं। लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था, तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1,000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं बनें, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है।

24 घंटे में दूसरी बार की अपील

पेट्रोल-डीजल का संयम से इस्तेमाल करें हालात सामान्य होने तक सोना नहीं खरीदें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का उद्घाटन के मौके पर देश से 24 घंटे के भीतर दूसरी बार वैश्विक संकट का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां, और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है।पीएम मोदी ने कहा कि मेरी देश के हर नागरिक से अपील है कि जहां तक संभव हो, पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है, वो एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है कि टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये

शुभेंदु अधिकारी ने पहले दिन लिए कई अहम फैसले

बॉर्डर पर बीएसएफ को मिलेगी जमीन, आयुष्मान भारत की शुरुआत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक सुधार, सीमाई सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसलों की घोषणा की। नवान्न में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब %सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार% के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम बंगाल को भाजपा शासित अन्य राज्यों की विकास नीति के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर के जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार के सिद्धांत पर काम करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर बाहर, भरोसा अंदर संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकार लोगों की सुरक्षा, विश्वास और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।कैबिनेट बैठक में सबसे अहम निर्णयों में सीमाई सुरक्षा को लेकर बीएसएफ को आवश्यक जमीन



सौंपने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का फैसला शामिल है। मुख्यमंत्री ने भूमि एवं राजस्व विभाग तथा मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों के हित में केंद्र और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी की थी।

सरकार ने राज्य को आधिकारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई।

सीएम अधिकारी को जान से मारने की धमकी

कोलकाता। बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को जान से मारने की सीधी धमकी मिलने का मामला सामने आया है। दी डेली इंकलाब नामक फेसबुक पेज पर प्रसारित एक वीडियो में एक मुस्लिम व्यक्ति को मुख्यमंत्री के विरुद्ध हिंसक और बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हिंदी में बोलते हुए कर रहा है। इस फेसबुक पेज पर मौजूद दी डेली इंकलाब नाम के साथ बांग्लादेश का झंडा है जिससे अनुमान लगाया रहा है कि उक्त वीडियो बांग्लादेश में बना है लेकिन बोलने वाला शख्स हिंदी साफ-साफ बोल रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। वायरल वीडियो में आरोपित व्यक्ति मुख्यमंत्री को सीमा पर ही दफनाने और उन पर शारीरिक हमला करने की धमकी दे रहा है। हालांकि, स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस वीडियो की प्रमाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में हुई हत्या के बाद इस तरह की धमकियों को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन्स रायपुर में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों के साथ बेहद सहज और प्रेरणादायी संवाद करते हुए उनके सपनों, पढ़ाई की दिनचर्या, सफलता के अनुभव और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री निवास का वातावरण इस दौरान उत्साह, प्रेरणा और आत्मीयता से भर उठा।

1 जुलाई से मनरेगा की जगह लेगा जी-रामजी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी जी-रामजी कानून लागू करने का फैसला किया है। नया कानून पहली जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही पुराना मनरेगा कानून समाप्त हो जाएगा।

सरकार का दावा है कि यह सिर्फ रोजगार योजना नहीं, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला नया विकास मॉडल है। सरकार इसे ग्रामीण विकास के नए दौर की शुरुआत के रूप में पेश कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि नए कानून से मजदूरों, किसानों एवं गांवों को ताकत मिलेगी। यदि सही तरीके से लागू हो गया तो यह योजना सिर्फ रोजगार गारंटी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों की बुनियादी संरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा भी दे सकती है।



सबसे बड़ा बदलाव रोजगार गारंटी के दिनों में हुआ है। अभी मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में सौ दिन काम का कानूनी अधिकार है। नई व्यवस्था में इसे 125 दिन कर दिया गया है। यानी श्रमिक परिवारों को अतिरिक्त 25 दिन काम मिलेगा। इससे गांवों में नकदी प्रवाह बढ़ने और श्रमिकों की आय में मजबूती आएगी।

व्यवस्था में बदलाव के दौरान मजदूरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। 30 जून तक चल रहे सभी काम नई योजना में अपने आप शामिल हो जाएंगे। मौजूदा जॉब कार्ड भी तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।नई योजना को विकसित भारत-2047 के विजन से जोड़ा गया है। फोकस सिर्फ गड्ढे खोदने या सीमित निर्माण कार्यों तक नहीं रहेगा। जल संरक्षण, सड़क, पुलिया, स्कूल भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, खेतों से जुड़े ढांचागत काम, बाढ़ सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़े स्थायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए वर्किंग शेड बनाई जा सकेंगी।

भुगतान प्रणाली को लेकर भी सरकार सजग दिख रही है। मजदूरी सीधे बैंक या डाकघर खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य तीन दिन के भीतर भुगतान का है, हालांकि अधिकतम सीमा 15 दिन तय की गई है। अगर मजदूरी में देरी हुई तो मजदूरों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा।

प्रमुख समाचार

क्या देश में आर्थिक आपातकाल है: केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों को एक साल तक सोने पर खर्च न करने और खाना पकाने के तेल की खपत कम करने के सुझाव पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए।



एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी को जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को खाने-पीने, यात्रा और पर्यटन पर खर्च कम करने और यहां तक कि सोने और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीद पर भी कटौती करने की सलाह दी है। क्या यह आर्थिक आपातकाल का संकेत है? क्या देश गंभीर आर्थिक संकट में डूबा हुआ है? देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। आखिर देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है? आप नेता ने सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र किया।

चीनी कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध अवैधः चीन

बीजिंग।चीन ने ईरान से संबंध होने के कारण चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले का विरोध करते हुए नयी नीतियों को 'अवैध' एवं अंतरराष्ट्रीय कानून का विरोधी करार दिया।चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुए जियाकुन ने सोमवार को कहा कि चीन अमेरिका द्वारा थोपे गये एकतरफा प्रतिबंधों को नकारता है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं है।उल्लेखनीय है कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने चीन और हांगकांग की कंपनियों एवं लोगों पर ईरान की सेना की सहायता करने का आरोप लगाते हुए उन पर प्रतिबंध लगाये हैं। इस सूची में शामिल 12 लोगों एवं कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने ईरान की सेना के इस्तेमाल के लिए हथियार एवं तकनीक खरीदी हैं। बीजिंग लगातार चीनी कंपनियों से यह अपेक्षा करता है कि वे कानूनों और नियमों के अनुसार ही अपना कारोबार करें, और वह चीनी उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की पूरी मज़बूती से रक्षा करने का इरादा रखता है। श्री गुओ ने कहा, जहां तक ईरान की स्थिति का सवाल है, चीन ने बार-बार इस पर अपना दृढ़ रुख स्पष्ट किया है। इस समय सबसे ज़रूरी काम यह है कि युद्ध को फिर से शुरू होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जायें।

उपदेश नहीं, सरकार की नाकामी के सबूतःराहुल

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता को त्याग और बचत की सलाह देना सरकार की विफलता को दर्शाता है। श्री राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ,



पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो और घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, बल्कि सरकार की नाकामी के सबूत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब सरकार जनता को यह बताने लगी है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, देश चलाना अब प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए ऊर्जा बचत, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के लिए लड़ना ही देशभक्ति नहीं है।

चुनाव खत्म होते ही सरकार को याद आया 'संकट': अखिलेश

लखनऊ।उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए सोमवार को कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को संकट याद आ गया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा संकट भाजपा ही है और केंद्र सरकार की हालिया



अपीलें उसकी आर्थिक व नीतिगत विफलताओं को उजागर करती हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि यदि इतनी पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं तो पांच ट्रिलियन डॉलर की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के हाथ से आर्थिक व्यवस्था की लगाम छूट चुकी है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है।अखिलेश यादव ने सोने की खरीद को लेकर सरकार की अपील पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जनता तो वैसे भी डेढ़ लाख तोले का सोना खरीदने की स्थिति में नहीं है, बल्कि भाजपा के लोग ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं।

सत्रहवीं तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र शुरू

चेन्नई। तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के संस्थापक सी. जोसेफ विजय ने भी सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। पूर्वाह्न 9.30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर एम. वी. करुप्पैया ने एक तिरुक्कुरल



का पाठ किया और विधानसभा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। जिन्हें रविवार शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई थी।इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, विपक्ष के नेता, डीएमके के उधयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पडी के. पलानीस्वामी और ओ. पन्नीरसेल्वम सहित अन्य सदस्यों को चुनाव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। अन्य विधायकों ने वर्णमाला क्रम में एक-एक कर शपथ ली। नौ नए मंत्रियों में से आठ ने शपथ ली, जबकि एकमात्र महिला विधायक एस. कीर्तन अपना प्रमाणपत्र लाना भूल गईं।

अग्निपरीक्षा साबित हो सकता है ट्रंप का चीन दौरा

वाशिंगटन। ईरान युद्ध, चीन के साथ बिगड़ते रिश्ते और दुनिया में एआई पर कब्जे की होड़ के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते चीन जा रहे हैं और यह दौरा उनके लिए अग्निपरीक्षा साबित हो सकता है।

श्री ट्रंप बुधवार शाम को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन के लिए बीजिंग पहुँचने वाले हैं। अमेरिका में कई लोगों को उम्मीद थी कि यह बैठक तब होगी जब ईरान युद्ध को स्थिर करने की दिशा में कुछ प्रगति हो चुकी होगी, जो वर्तमान में एक अस्थिर युद्धविराम के दौर में है।

इस बीच ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका को एक पन्ने का ज्ञापन सौंपा था, लेकिन श्री ट्रंप ने इसे %अस्वीकार्य% बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने ईरान पर %खेल खेलने% का भी आरोप लगाया था। इस स्थिति के कारण बीजिंग शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस के सामने मुश्किलें खड़ी हो गयी हैं।

हालांकि, यह शिखर सम्मेलन केवल ईरान वार्ता से कहीं अधिक महत्व रखता है। श्री ट्रंप पर भारी दबाव है कि वह श्री जिनपिंग के सामने या तो नए सिरे से रिश्ते तय करें, तनाव बढ़ाएं या फिर खाली हाथ लौट आएं। श्री ट्रंप के राजनीतिक सहयोगी श्री जिनपिंग के साथ इस सीधी मुलाकात को उनके राष्ट्रपति काल के सबसे निर्णायक राजनयिक क्षणों में से एक मान रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने इस यात्रा को अत्यधिक प्रतीकात्मक महत्व वाला बताया है।

राजनयिक औपचारिकताओं के पीछे एक बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियाँ आपसी दुश्मनी को इस तरह संभाल सकती हैं कि वे लंबे समय तक



आर्थिक अलगाव या सैन्य टकराव की स्थिति में न पहुँचें। श्री ट्रंप के साथ प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ का एक समूह भी बीजिंग जा रहा है, ताकि निवेश सुरक्षित किया जा सके और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में तनाव कम हो सके।हालांकि, हाल के हफ्तों में ईरान युद्ध के कारण रिश्ते और भी खराब हुए हैं। ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को तीन चीनी सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में ईरानी सेना की मदद की थी। चीन ने भी हालांकि झुकने से इनकार करते हुए %ब्लॉकिंग कानून% लागू कर दिया, जिससे चीनी कंपनियों को ईरानी तेल खरीद से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों को अनदेखा करने का निर्देश मिल गया।इसी बीच, ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच सबसे खतरनाक और अनसुलझे विवाद के रूप में बना हुआ है। यह द्वीप न केवल सैन्य टकराव का केंद्र है, बल्कि सेमीकंडक्टर उद्योग का भी केंद्र है जो वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था को शक्ति देता है। अमेरिका के दोनों दलों के आलोचकों को डर है कि श्री ट्रंप की व्यक्तिगत कूटनीति और बड़े सौदों की प्राथमिकता ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन को कमजोर कर सकती है।

एआई सुरक्षा के जोखिमों पर भी दोनों नेताओं के बीच पहली बार सीधी चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस अब एआई सुरक्षा पर चीन के साथ औपचारिक संचार चैनल बनाने पर विचार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे शीत युद्ध के दौरान परमाणु खतरों को कम करने के लिए %हॉटलाइन% बनाई गई थी। यह चर्चा तब हो रही है जब अमेरिका लगातार चीन पर अमेरिकी एआई कंपनियों से तकनीक और शोध चुराने के आरोप लगा रहा है

बीजापुर में जमीन के अंदर नक्सलियों का बंकर

■ सर्चिंग ऑपरेशन में जमीन के अंदर मिला नक्सलियों का डंप, ग्रेनेड लॉन्चर, जनरेटर जैसे सामान



बीजापुर। जिले में पुलिस को नक्सलियों का एक बंकर मिला है जहां से विस्फोटक सामग्री, हथियारों समेत कई घातक सामानों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। मामला गंगालूर थाना इलाके के गांव डोडीतुमनार का है। एएसपी रविंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए जानकारी दी। ग्राम डोडीतुमनार के पटेलपारा स्थित पहाड़ी एवं घने जंगल क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस सहायता केंद्र पीडिया एवं थाना गंगालूर की संयुक्त टीम ने सघन सर्चिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान जवानों को जंगल में जमीन के अंदर छिपाकर बनाया गया नक्सलियों का एक बंकर मिला। बंकर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार एवं उपयोगी उपकरण बरामद किए गए। इनमें एक देशी बीजीएल लॉन्चर, 29 बीजीएल सेल, लगभग 50 मीटर कॉर्डेक्स वायर और दो प्लास्टिक ड्रम मिले। वहीं बरामद सामग्री में दो होंडा कंपनी के जनरेटर, दो लेथ मशीन, एक इन्वर्टर, चार बड़ी और एक छोटी बैटरी के साथ 8 सोलर प्लेट भी मिली है। इसके अलावा एक मोटर, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन भी छिपाकर रखी गई थी। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि नक्सली इन सामग्रियों का उपयोग विस्फोटक तैयार करने एवं तकनीकी कार्यों के लिए करते थे। पुलिस द्वारा बरामद सभी सामग्रियों को जब्त कर लिया गया है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।

पांच लाख की ईनामी लक्ष्मी ने किया सरेंडर



जगदलपुर। छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश के बॉर्डर पर लंबे समय से सक्रिय डीकेएसजेडसी सदस्य लक्ष्मी ने आंध्रप्रदेश के अल्लुरी सीताराम राजू जिले में पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके इस कदम से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। लक्ष्मी पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। आंध्रप्रदेश के अल्लुरी सीताराम राजू के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। महिला नक्सली पोडियम लक्ष्मी बीजापुर जिले के उसुर थाना क्षेत्र की निवासी थी। वह डीकेएसजेडसी की सदस्य थी और लंबे समय से छत्तीसगढ़ व आंध्रप्रदेश बॉर्डर में सक्रिय थी। उसने पुलिस अधिकारियों के समक्ष हथियार डाले। पुलिस अधिकारियों ने उसे मुख्यधारा में जोड़ते हुए पुनर्वास राशि भी सौंपी।

खोंधरा जंगल में कई चीतलों की हो चुकी है मौत

खोंधरा जंगल में वन्यजीवों की सुरक्षा पर उठे सवाल



बिलासपुर। बिलासपुर के सीपत क्षेत्र अंतर्गत खोंधरा जंगल में वन्यजीवों की मौत पर अब सवाल उठने लगे हैं।पिछले 9 माह में करीब 7 चीतलों की मौत हुई है।इसके बाद भी वन विभाग इनके संरक्षण और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से गंभीर नहीं दिख रहा है। खोंधरा जंगल में एक नर चीतल का शव मिलने के बाद क्षेत्र में फिर से वन्यजीव सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है।

स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन लोगों का आरोप है कि विभाग समय रहते निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था करने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल में भीषण गर्मी के दौरान वन्यजीवों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से चीतल और अन्य वन्यजीव गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। पानी की तलाश में बस्तियों के आसपास पहुंचने पर आवारा कुत्तों के हमले में उनकी मौत हो रही है। लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले 9 महीनों में कुत्तों के हमले से करीब 7 चीतलों की जान जा चुकी है। डेढ़ महीने पहले सोंठी क्षेत्र में एक गर्भवती मादा चीतल की मौत का मामला भी सामने आया था। इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खोंधरा का जंगल अब शिकारियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनता जा रहा है। देर रात बाहरी क्षेत्रों से आने वाले शिकारी जंगल में सक्रिय रहते हैं, लेकिन वन विभाग की गश्त और कार्रवाई नजर नहीं आती। लोगों का कहना है कि कई मामलों को दबा दिया जाता है और केवल सामने आने वाली घटनाओं पर औपचारिक कार्रवाई की जाती है।

एसडीएम दफ्तर का रिश्वतवतखोर बाबू अरेस्ट,एसीबी की कार्रवाई



बिलासपुर । एसडीएम दफ्तर के बाबू को 15 हजार की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने अरेस्ट किया है। आरोपी बाबू ने प्रार्थी को जुर्माने की रकम करने का लालच देकर घूस की मांग की थी।लेकिन प्रार्थी आरोपी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।इसलिए उसने इसकी जानकारी एसीबी को दी और एसीबी ने आरोपी को ट्रैप किया। एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने रविवार को जिला मुख्यालय स्थित अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने सहायक ग्रेड-3 विजय पांडेय को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लंबित प्रकरण में जुर्माना राशि कम कराने रिश्वत की मांग की थी। आपको बता दें कि करगी रोड कोटा के रहने वाले होटल संचालक देवेंद्र कश्यप ने एसीबी कार्यालय बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। अगस्त 2025 में उसके होटल की जांच के दौरान खाद्य पदार्थ पेड़ा खुले में पाया गया था।इसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर ने देवेंद्र कश्यप के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण बनाकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया था। शिकायत में बताया गया कि एडीएम कार्यालय में तैनात बाबू विजय पांडेय ने जुर्माना राशि 1 लाख रुपए तक होने की बात कहकर मामले को 30 हजार रुपए में निपटाने का भरोसा दिया।लेकिन इसके बदले 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की।सत्यापन के दौरान आरोपी पहले ही 5 हजार रुपए ले चुका था, जबकि बाकी 15 हजार रुपए लेना बचा था। एसीबी ने शिकायत सही पाए जाने के बाद ट्रैप की योजना बनाया।इसी बीच रविवार को आरोपी ने शिकायतकर्ता को एडीएम कार्यालय बुलाया जहां प्रार्थी से 15 हजार रुपए लेते ही एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली। एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ लगातार रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं।जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई कर जांच पड़ताल कर रही है।

पीएलजीए का गढ़ रहे सुकमा के गुंडराजगुड़ेम में पहली बार पहुंची बिजली

■ आजादी के बाद पहली बार सुकमा के गुंडराजगुड़ेम गांव में बिजली पहुंची. पहली बार वहां के ग्रामीणों ने अपने गांव में लाइट देखी.



सुकमा। जिले के गुंडराजगुड़ेम गांव में पहली बार बिजली पहुंची। जब घरों में बल्ब जले तो बच्चों ने ताली बजाई, महिलाएं खुशी से मुस्कुरा उठीं। वहीं लंबे समय से बिजली का इंतजार कर रहे बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों ने यह तक कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके गांव में भी एक दिन बिजली पहुंचेगी। सुकमा बीजापुर सीमा पर गुंडराजगुड़ेम गांव है। पहले यह गांव माओवादियों के [illegible] बटालियन-1 का मजबूत गढ़ माना जाता था। माओवादियों की इतनी दहशत थी कि इस गांव का नाम सुनते ही लोग सहम जाया करते थे। जंगलों में बारूदी सुरंगें, हर कदम पर खतरा और रात होते ही गोलियों की गूंज इस इलाके की पहचान थी। अब उसी गुंडराजगुड़ेम में पहली बार बिजली के बल्ब जले हैं। अंधेरे में डूबे गांव में जब रोशनी फैली, तो ग्रामीणों की आंखों में सिर्फ चमक नहीं, बल्कि वर्षों का दर्द और उम्मीद दोनों दिखाई दिए। रविवार का दिन गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुरक्षा बलों और प्रशासन के प्रयासों के बाद ट्रांसफार्मर लगा और बिजली लाइन का काम पूरा हुआ और आजादी के बाद पहली बार गांव में बिजली पहुंची। जिस गांव में कभी माओवादी विकास कार्यों का विरोध करते थे, वहां अब बच्चे रोशनी में पढ़ाई करेंगे और घरों में पहली बार पंखे चलेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में सालों तक सड़क निर्माण, मोबाइल टॉवर, बिजली लाइन को नक्सली निशाना बनाते थे।

काम करने वाले ठेकेदारों और मजदूरों को धमकियां दी जाती थी। मशीनें जलाई गईं और निर्माण कार्य रोक दिए गए। नक्सल अभियान में तेजी के बाद पिछले कुछ वर्षों में हालात बदले। जिला पुलिस सुकमा और [illegible] ने लगातार इस इलाके में अभियान चलाया।

चलती ट्रेन में चढ़ते फिसला यात्री आरपीएफ जवान ने बचाई जान

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक यात्री चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक निरंजन ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक यात्री चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक निरंजन ने तत्परता दिखाते हुए यात्री की जान बचाई। यह घटना प्लेटफॉर्म चार पर हुई, जब बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस रवाना हो रही थी। एक यात्री जल्दबाजी में चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। ट्रेन धीरे-धीरे गति पकड़ रही थी, तभी यात्री का पैर फिसल गया। वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के अंतर में जा फंसा। घटना देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं।

भूपेश सरकार ने दी थी अडानी को एनओसी : मंत्री जायसवाल

■ सरगुजा में पेड़ों की कटाई पर मंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री ने सरकार में रहकर इसका विरोध नहीं किया अब सवाल उठा रहे हैं



मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा में पेड़ों की कटाई और अडानी ग्रुप को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। चिरमिरी पहुंचे मंत्री जायसवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरगुजा संभाग के वरिष्ठ नेता होने के नाते सिंहदेव को जनता के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरगुजा क्षेत्र में लगभग 7 लाख पेड़ काटे जाने को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस मामले में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अडानी ग्रुप को एनओसी (हस्तांतरण) तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में दी गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय टीएस सिंहदेव खुद सरकार में मंत्री थे और यदि उन्हें इस परियोजना से आपत्ति थी तो उसी समय विरोध दर्ज कराना चाहिए था। मंत्री जायसवाल ने कहा कि आज जनता के बीच जाकर केवल बयानबाजी करना उचित नहीं है। अगर उस समय सरकार के भीतर रहकर इसका विरोध किया जाता तो शायद आज ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को हवा देने का आरोप भी लगाया। श्याम बिहारी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास और पर्यावरण के संतुलन की बात करती है। सरकार जनता के हितों और पर्यावरण संरक्षण दोनों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।

नहाते ग्रामीण पर जानलेवा तेंदुए का हमला

जगदलपुर। कांकेर जिले के सरोना परिक्षेत्र में एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला कर दिया। यह घटना तब हुई जब ग्रामीण अपने खेत के बोर में नहा रहा था। इस हमले के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग वन्यजीवों के प्रति भयभीत हैं। कांकेर जिले के बांगाबारी नयापारा गांव निवासी सगराम नेताम रविवार की शाम को अपने खेत के बोर में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक एक तेंदुए ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अपने ऊपर हुए अचानक हमले में ग्रामीण सगराम ने मदद के लिए जोर से चीख-पुकार की। उनकी आवाज सुनकर पास ही में काम कर रहे अन्य ग्रामीण तुरंत मौके पर आ पहुंचे। ग्रामीणों को अपनी ओर आता देख तेंदुआ मौके से भाग निकला। घायल सगराम को आसपास के लोगों ने तुरंत पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि यह पूरा क्षेत्र वन परिक्षेत्र सरोना के अंतर्गत आता है। इस इलाके में वन्यजीवों की आवाजाही सामान्य है। हालांकि, इस तरह का सीधा हमला चिंताजनक है। ग्रामीणों में अब अपने खेतों में काम करने को लेकर डर बैठ गया है। घायल ग्रामीण सगराम नेताम की हालत अभी ठीक बताई जा रही है। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासनवाही लाया गया। डॉक्टरों ने उनकी चोटों का इलाज किया और उन्हें निगरानी में रखा है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीण अब अपने खेतों में अकेले जाने से भी डर रहे हैं, खासकर शाम के समय और अंधेरा होने के बाद। वन विभाग को इस घटना की सूचना दे दी गई है। विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्हें रात के समय अकेले बाहर न निकलने और समूह में रहने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने और क्षेत्र में ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। विभाग ने गश्त बढ़ाने और वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जगदलपुर में विशाल प्लेसमेंट कैंप, 305 पदों पर सीधी भर्ती

जगदलपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर की तरफ से मंगलवार 12 मई को एक दिवसीय विशाल प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। जिसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां 305 अलग अलग पदों पर योग्य युवाओं का चयन करेगी। इस भर्ती अभियान के तहत पैरामाउंट ह्यूमन रिसोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन के 300 पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है। जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं, 12 वीं व इलेक्ट्रिकल व वायरिंग में आईटीआई निर्धारित की गई है। इस पद के लिए चयनित युवाओं को 16,500 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कायजेन मोटोवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेल्स ऑफिसर के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए कार्यक्षेत्र जगदलपुर, कोण्डागांव और दंतेवाड़ा तय किया गया है। जहाँ चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त होगा।

जिले के कमोदा बिहार रिसॉर्ट अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

सरगुजा। सरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर में कमोदा बिहार रिसॉर्ट से लगी सरकारी जमीन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार सुबह बुलडोजर चलाकर लगभग 45 डिसमिल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान वहां बने शेड, बाउंड्री और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। रिसॉर्ट संचालकों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर व्यावसायिक उपयोग के लिए शेड और बाउंड्री का निर्माण किया था। राजस्व विभाग की नापजोख में यह अवैध कब्जा पाया गया था। पूर्व में नोटिस जारी होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया था। सोमवार सुबह छह बजे प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सुबह सात बजे बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हुई, जो करीब चार घंटे तक चली। रिसॉर्ट परिसर के बड़े शेड सहित अन्य अवैध निर्माण तोड़े गए। एक अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए कमरों को भी ध्वस्त किया गया। एसडीएम वन सिंह नेताम ने बताया कि अतिक्रमण का मामला तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन था। जांच में कब्जा सही पाए जाने के बाद बेदखली नोटिस जारी किया गया था।

धान खरीदी के नाम पर अवैध वसूली, कलेक्टर से शिकायत

खैरागढ़। जिले के विचारपुर धान खरीदी केंद्र से सामने आए एक कथित वीडियो ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद किसान परिवार ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर और सहकारिता विभाग से की है। शिकारीटोला निवासी किसान देविका सिन्हा का परिवार 270 बोरा धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचा था। आरोप है कि धान जांच के दौरान केंद्र प्रबंधन ने गुणवत्ता खराब बताते हुए धान खरीदने से इनकार कर दिया और कहा धान वापस ले जाओ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी दौरान धान खरीदी कराने के बदले पैसों की मांग की गई। शिकायतकर्ता तुलेश सिन्हा के अनुसार बातचीत के दौरान 10 से 15 हजार रुपए तक की मांग की बात कही गई। इसी बीच उन्होंने मोबाइल से कथित बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि धान खरीदी प्रभावित न हो, इसलिए किसान परिवार ने कथित तौर पर 300 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए, जबकि 150 रुपए नगद दिए गए।

लेनदारों से छुटकारा पाने चोरी की रची झूठी कहानी

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में चौकाने वाला मामला सामने आया कि शिकायतकर्ता ने अपने ही घर में चोरी की झूठी साजिश रची थी और यह सब उसने लेनदारों से छुटकारा पाने के लिए किया था। यह पूरा मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है। दरअसल, बनडभरा गांव में रहने वाले नरेश भरद्वाज ने 9 मई को थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 8 मई को उसने 2 लाख 21 हजार रुपए में अपना खेत बेचा था। इस पैसे को उसने घर के अलमारी में रखा था और खुद घर के आंगन में सोया था। रात में किसी ने घर में घुसकर अलमारी को पार कर लिया और पास के खेत में ले जाकर उसमें से पैसे निकाल लिए।घटना की शिकायत के बाद वो थाना आने और फोन उठाने में आना कानी करने लगा, जिसके बाद टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की और नरेश से भी कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। उसने गांव के कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, जिसे वापस देना ना पड़े इसलिए उसने ये झूठी साजिश रची थी।

शारदा सिनेमा हाल में जन गोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन

बीजापुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय बीजापुर के शारदा सिनेमा हाल में एक दिवसीय प्रमुख जन गोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलेभर से सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, युवाओं सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, सेवा कार्य एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कणिराम ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र साधना और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपरा और हिंदू दर्शन आज पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है, तथा समाज के सामूहिक पुरुषार्थ से राष्ट्र चेतना निरंतर मजबूत हो रही है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज और राष्ट्रहित के कार्यों में आगे आएं तथा सेवा, संस्कार और संगठन की भावना को आत्मसात करें।

नारायणपुर में डीजल संकट गहराया: चार पेट्रोल पंपों में स्टॉक खत्म



नारायणपुर। जिले के पांच पेट्रोल पंपों में से चार पर डीजल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है, जबकि एकमात्र संचालित पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों, ट्रैक्टर संचालकों, माइंस परिवहन और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को हो रही है। डिब्बों में डीजल नहीं मिलने से नाराज किसान और ट्रैक्टर चालक डिब्बे लेकर कलेक्टर निवास पहुंच गए। नारायणपुर जिले में अचानक गहराए डीजल संकट ने आम जनजीवन से लेकर कृषि और परिवहन व्यवस्था तक को प्रभावित कर दिया है। एकमात्र पेट्रोल पंप पर डीजल लेने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से लेकर देर रात तक वाहन चालक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित किसान वर्ग हो रहा है। हाल ही में हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद खेतों की जुताई का काम शुरू होना था, लेकिन ट्रैक्टरों में डीजल नहीं होने के कारण कृषि कार्य ठप पड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में डीजल की कमी से उनकी पूरी तैयारी प्रभावित हो रही है। डीजल नहीं मिलने से नाराज किसान और ट्रैक्टर संचालक डिब्बे लेकर कलेक्टर निवास पहुंच गए। उनका कहना है कि पेट्रोल पंप संचालक डिब्बों में डीजल देने से मना कर रहे हैं और कलेक्टर की अनुमति लाने की बात कह रहे हैं। इसी वजह से ग्रामीण और किसान अपनी समस्या सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर आवास पहुंचे। हालांकि सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद लोगों ने बाहर ही डेरा डाल दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई छोटे व्यापारी गन्ना जूस मशीन जैसे उपकरण डीजल से चलाते हैं। ऐसे उपकरणों को पेट्रोल पंप तक लाना संभव नहीं होता, इसलिए वे डिब्बों में डीजल लेकर जाते हैं। इसके अलावा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कई ट्रैक्टर खेतों में ही खड़े रहते हैं और उन्हें 30 से 50 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप तक लाना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है। कई बार ट्रैक्टरों में डीजल पूरी तरह खत्म हो जाता है, ऐसे में डिब्बों के माध्यम से ही गांव तक डीजल पहुंचाया जाता है। डीजल संकट का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है। जिले में चल रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और अन्य विकास कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहन डीजल के अभाव में खड़े हो रहे हैं।वहीं माइंस परिवहन से जुड़े ट्रकों के पहिए भी थमने लगे हैं। नारायणपुर क्षेत्र में संचालित माइंस से जुड़े ट्रांसपोर्ट कार्य प्रभावित होने लगे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है।

आरआई पटवारी को ग्रामीणों ने बनाया बंधक



कोरबा। कोरबा में करतला थाना क्षेत्र के नोनबिर्रा गांव में जमीन सीमांकन के दौरान जमकर विवाद हुआ। गलत नापी का आरोप लगाकर परिजनों ने राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी को बंधक बना लिया। पटवारी भरत चौहान ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वे राजस्व निरीक्षक जयपाल सिंह के साथ 8 मई को नोनबिर्रा के बनियापारा पहुंचे थे। न्यायालय नायब तहसीलदार करतला के आदेश पर आवेदक संतराम की भूमि का सीमांकन किया जा रहा था। विधिवत सूचना के बाद खसरा नंबर 643 के सभी बटांकन की नाप कर जानकारी दी गई। दोपहर करीब एक बजे आवेदक संतराम, पुत्र लीलाधर पटेल, हुकुम चंद और हरिराम ने सीमांकन पर आपत्ति जताई। उन्होंने विवाद शुरू कर दिया और अधिकारियों की कार का रास्ता रोक दिया। करतला थाना पुलिस ने पटवारी भरत चौहान की रिपोर्ट पर संतराम, लीलाधर पटेल, हरिराम और हुकुमचंद पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों ने राजस्व निरीक्षक और पटवारी को गाली-गलौज की। उन्होंने गलत नापी और पैसे लेकर सीमांकन का आरोप लगाया। पुत्र लीलाधर ने रस्सी से खुदकुशी कर फंसाने की धमकी दी। परिवार ने अधिकारियों को करीब दो घंटे तक बंधक बनाए रखा। शासकीय कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी भी दी गई।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने हाटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सोमवार को राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने महादेव से राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय आज हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर महादेव घाट में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने पहुंचे थे।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने भोरमदेव मंदिर में की पूजा



रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए भोरमदेव मंदिर परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने भोरमदेव में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और जिलेवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, रामकिंकर वर्मा, विजय पाटिल, उमंग पाण्डेय, मनीराम साहू, लोकचंद साहू, रूपसिंह धुर्वे,रूपसिंह मरावी, रामजी मरावी, काशीराम उइके, आदित्य श्रीवास्तव, भूखन साहू, हेमचंद्र चंद्रवंशी, मिलूराम साहू, परदेशी पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि ने भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया।

लक्ष्य ज्वेलर्स में एक करोड के सोने-चांदी के जेवरात पार

रायपुर। खम्हारडीह इलाके में स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए वहां से करीब एक करोड रुपए के सोने-चांदी के जेवरात पार कर फरार हो गए। फिलहाल खम्हारडीह पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 12ः30 बजे चोर लक्ष्य ज्वेलर्स शॉप में घुसे और डिस्प्ले काउंटर में रखे कीमती आभूषण चोरी कर फरार हो गए। रविवार को दुकान बंद होने के कारण कारोबारी को घटना की जानकारी नहीं मिल सकी। सोमवार सुबह दुकान खोलने पर चोरी का खुलासा हुआ।घटना की सूचना मिलते ही खम्हारडीह थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।

पीडब्ल्यूडी और सामान्य प्रशासन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर होगी भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में 46 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल जबकि सामान्य प्रशासन विभाग में सिविल में भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, 13 मई को दोपहर 12 बजे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छूक अभ्यर्थी 11 जून, रात 11.59 बजे तक सीजीपीएससी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा की संभावित तारीख 16 अगस्त है। अभ्यर्थी आवेदन में त्रुटि सुधार 12 से 14 जून तक कर सकेंगे। सशुल्क त्रुटि सुधार 15 से 17 जून तक किए जा सकेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल, यांत्रिकी या विद्युत में बीई / बीटेक उपाधि हो वे आवेदन कर सकते है। अभ्यर्थी की उम्र 21 से 30 वर्ष तक (1 जनवरी 2026 की स्थिति में) होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष होगी। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु 45 वर्ष है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 150-150 अंकों के दो बहु विकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे। इसमें पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा इंजीनियरिंग का होगा। पदों का विवरण- असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) : 42 पद, असिस्टेंट इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिकी): 3 पद, असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल): 1 पद।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सनातन संस्कृति को मिला नया गौरव : साय

राजधानी रायपुर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पूजा - अर्चना का अवलोकन कर उनका संबोधन सुना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सोमनाथ मंदिर के स्वर्णिम इतिहास, विदेशी आक्रांताओं द्वारा किए गए हमलों, मंदिर के पुनरनिर्माण यात्रा, वर्तमान सरकार द्वारा किये जा रहे आस्था के केंद्रों का संरक्षण एवं संवर्धन के संकल्प सहित विभिन्न विषयों पर अपनी बातें देशवासियों से साझा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर अनेक बार बाहरी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन मंदिर की आस्था और परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका। श्री साय ने कहा कि पहली बार आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर नहीं छोड़ा तथा अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।

श्री साय ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने तमाम विरोधों के बावजूद सोमनाथ मंदिर पहुंचकर पुनर्निर्मित मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया था। श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को नया गौरव मिला है। उन्होंने कहा कि आज देशभर के प्रमुख तीर्थ स्थलों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बनारस के काशी विश्वनाथ, उज्जैन स्थित महाकाल से लेकर सोमनाथ मंदिर तक व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देवी माताओं के मंदिरों को शक्तिपीठ योजना के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इसी तरह कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव महादेव मंदिर को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और यहां पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि और भगवान श्रीराम का ननिहाल है। सनातनियों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या के मंदिर में भगवान श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 40 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं और यह योजना लगातार जारी है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में सभी लोगों से भाईचारे, सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सनातन संस्कृति और आस्था केंद्रों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुखिया भी प्रदेश में धार्मिक स्थलों के संरक्षण के साथ ही विभिन्न योजनों के माध्यम से लोगों को आस्था से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर देश की संस्कृति, वैभव और स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सल उन्मूलन के बाद पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को नई गति मिली है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि सोमनाथ मंदिर सनातनियों के आस्था का बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि हजार वर्षों के इतिहास में अनेक आक्रमणों के बावजूद सनातन संस्कृति की आस्था को कोई डिगा नहीं पाया है और न कभी ऐसा होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा, छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पीएम मोदी की अपील पर सीएम साय का बयानः कहा-

सोना कम खरीदें और पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करें, राहुल के बयान पर भी किया पलटवार



रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे देशहित में ईंधन की बचत करें और अगले एक वर्ष तक शादियों के लिए सोना खरीदने से बचें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा पीएम मोदी की अच्छी सलाह।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि पश्चिम एशिया में वार की स्थिति है। सभी देशों को असर हो रहा है। कोई देश अछूता नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने अच्छी सलाह दी है। विदेश में हमारे देश का पैसा ना जाए, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। सोना कम खरीदें और पेट्रोल-डीजल का भी कम उपयोग करें।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत बता रहे हैं। इस बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नाकामी नहीं है अगर ऐसा है तो वे उपाय बताएं कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए।

तेलंगाना में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े आर्थिक और सप्लाई चेन संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में पिछले दो महीनों से चल रहे युद्ध और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों पर भारी दबाव बना हुआ है, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे अगले एक साल तक शादियों के लिए सोना न खरीदें। हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर विशेष ध्यान देना होगा। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कोरोना काल में देश ने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में फिर से इन विकल्पों को प्राथमिकता देना समय की मांग है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ईंधन की बचत करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा दुनिया भर में तेल बेहद महंगा हो चुका है। इसलिए हमें जरूरत के अनुसार ही ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए और अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए।

कच्चे से पक्के मकान के सपनों को विष्णु देव साय के सुशासन ने किया साकार



रायपुर। छत्तीसगढ़ की शांत और हरित वादियों के बीच बसे जशपुर जिले के ग्राम पंचायत चंदागढ़ का विकास आज पूरे प्रदेश को प्रेरित कर रहा है। यह उस बदलाव की गाथा है, जो एक संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व से ही संभव हो सकता है। गरीबों के सपनों के साकार होने की, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की और शासन की योजनाओं के धरातल पर उतरने की कहानी है चंदागढ़। इस विकास के केंद्र में हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास लोगों के जीवन में महसूस किया जा रहा है।

जशपुर जिले के पत्थलगांव जनपद पंचायत के तहत ग्राम पंचायत चंदागढ़ में सैकड़ों लोगों का वर्षों पुराना सपना आज साकार हुआ है। कभी कच्ची झोपड़ियों में जीवन बिताने के लिए मजबूर परिवार आज पक्के मकानों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गांव के कुल 304 हितग्राहियों को मकान स्वीकृत हुए जिनमें से 245 मकान सम्पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुके हैं। इस निर्माण से 245 परिवारों के जीवन में आने वाली स्थिरता, साय सरकार के सुरक्षा का प्रतीक है। चंदागढ़ निवासी भवन साय जैसे बहुत से परिवार जो वर्षों तक कच्चे मकानों में बारिश, ठंड और गर्मी की मार झेलते रहे, वे आज पक्के घरों में सुकून से रह रहे हैं। बरसात के दिनों में टपकती छत और असुरक्षा का भय अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ में होने वाला यह परिवर्तन बताता है कि जब शासन की योजनाएं सही दिशा, सही नेतृत्व और नीयत के साथ लागू होती हैं तो वो समाज की सबसे निचली पंक्ति तक पहुंचती हैं।

सुशासन तिहार पर सियासत

कांग्रेस ने बताया महज औपचारिकता, तो मंत्री ने लिया आड़े हाथ



रायपुर। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए मनाए जा रहे सुशासन तिहार को सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे पूरी तरह से फेल बता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने इस पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस शासनकाल में योजनाओं पर लगे ग्रहण की याद दिलाई है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सुशासन तिहार को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि यह महज औपचारिकता है। ये जनता के बीच में जाकर टाइम पास करने, नौटंकी करने जा रहे हैं। हकीकत यह है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को पीएम आवास के लिए दंडवत होना पड़ रहा है। अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। दरअसल, इन्होंने जनता के लिए कुछ काम ही नहीं किया है, ऐसे में अब जब पोल खुल रही है तो अधिकारी को धमका रहे हैं। सुशासन तिहार पूरी तरह से फेल है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज के सुशासन तिहार को लेकर दिए बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि आवास के लिए कांग्रेस सरकार ने 5 साल लोगों को तरसाया। आज़ादी के बाद आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया। हमारी सरकार ने 18 लाख से ज़्यादा पीएम आवास स्वीकृत किया है। आज आदिवासी की बात कर रहे, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और आवास तक पर नक्सलियों ने बुरी नजर लगाई, तब कांग्रेसियों के मुंह क्यो बंद थे।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोना नहीं खरीदने और वर्क फ्रॉम होम करने की अपील पर दीपक बैज ने कहा कि ये नाकामी का संदेश है। मोदी सरकार ने देश में महंगाई को चरम पर ला दिया। आज इसी दो महीने के अन्दर सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई। जरूरत की हर चीच के दाम आसमान छू रही है। राहुल गांधी कहते आए कि महंगाई चरम पर है, और आप उपदेश दे रहे हैं। मोदी ने खुद स्वीकार किया है कि महंगाई चरम पर है।

वहीं प्लास्टिक की बोतल में शराब मिलने पर दीपक बैज ने कहा कि पिछले एक तारीख से प्लास्टिक बोतल में शराब बिक रही है। चूहे प्लास्टिक बोतल भी कुतरते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जो माल निकलेगा दुकान तक पहुंचेगा ही नहीं। सब पैसा मंत्री खाएंगे, और इल्ज़ाम चूहों पर लगेगा।

आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला स्वास्तिक गिरफ्तार





रायपुर। रायपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी स्वास्तिक अग्रवाल को तेलीबांधा पुलिस ने पीडब्ल्यूडी ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से सट्टेबाजी में इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल फोन जब्त किया गया है जिसमें वह गूगल के माध्यम से रेडीबुक डॉट ग्रीन वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर से आईडी बनाई थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ का जा रही है।

तेलीबांधा पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ मुखबिर से सूचना मिली थी और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके पीडब्ल्यूडी ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गूगल के माध्यम से रेडीबुक डॉट ग्रीन वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर से आईडी बनाई थी। उसका यूजर नेम स्वस्तिक29 था। इसी आईडी के जरिए वह आईपीएल मैचों में हार-जीत पर रुपए का दांव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खेलता था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसके परिचित खरोरा निवासी चेतन ने क्रिकेट मैच में सट्टा खेलने के लिए उससे आईडी मांगी थी। इसके बाद उसने अपनी आईडी चेतन को दे दी। चेतन ने उसी आईडी पर अलग पासवर्ड बनाकर आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खेलना शुरू कर दिया।

पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल फोन में स्वस्तिक29 नाम की आईडी एक्टिव मिली। मोबाइल में ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े कई डिजिटल सबूत भी पाए गए। इसके बाद पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के कब्जे से सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। आरोपी चेतन की तलाश पुलिस कर रही है।

बेटिंग साइट का पैनल और लिंक बेचने के आरोप में लोकेश गिरफ्तार

रायपुर। दो सट्टेबाजों को बेटिंग साइट का पैनल और लिंक बेचने के आरोप में आजाद चौक पुलिस ने रामसागरपारा के लोकेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट की जांच कर रही है।

एसीपी आजाद चौक ईशु अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया कि आरोपी लोकेश अग्रवाल की गिरफ्तारी से ऑनलाइन सट्टे के सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है जो मास्टर पैनल संचालक था।

अग्रवाल ने बताया कि 4 अप्रैल को कबीरनगर पुलिस ने आकाश टांडी 31 वर्ष मस्जिद के पास कोटा और मोहम्मद आरिफ 50 वर्ष कोटेश्वर नगर कोटा को परमानंद नगर रेलवे ट्रैक के पास से गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 4 स्मार्ट फोन और करीब 5 लाख कैश जब्त किए ग। दोनों से पूछताछ और मोबाइल के फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि ये लोकेश अग्रवाल से आईडी लेकर काम करते थे, हालांकि दोनों आरोपियों के गिरफ्तार होते ही लोकेश अग्रवाल फरार हो गया था। आरोपी से जब्त दो सेलफोन की जांच में कई राज खुलने की उम्मीद है।

दुर्ग के 4 युवक लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर नकली टिकट बनाकर बेचते गिफ्तार

रायपुर। दुर्ग के 4 आरोपी युवकों को आईपीएल मैच के दौरान लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर चैटजीपीटी से नकली टिकट बनाकर बेचते हुए लखनऊ जिले की साइबर सेल और सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी आईपीएल टिकट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और प्रिंटिंग सामग्री बरामद क हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में दुर्ग निवासी श्रीकांत बोरकर, नूतन कुमार साहू, राजेंद्र चौधरी और विश्वजीत साहू शामिल है।

लखनऊ पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ सुपर जॉइंट और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 7 मई को मैच खेला गया था। इस मैच को देखने के लिए जालौन निवासी प्रदीप सिंह स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम के बाहर आरोपियों ने उन्हें दो टिकट बेचे और यूपीआई के जरिए 1000 रुपए ले लिए। लेकिन एंट्री गेट पर टिकट स्कैन होते ही उसे



फर्जी बताया गया। इसके बाद पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और तकनीकी जांच के आधार पर लखनऊ के दोदनखेड़ा चौराहे के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया से असली टिकटों की फोटो डाउनलोड करते थे। इसके बाद कॉरल ड्रा की मदद से हूबहू नकली टिकट तैयार करते थे। टिकट डिजाइन, साइज और पेपर क्वॉलिटी की जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों ने चैटजीपीटी का भी सहारा लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आर्थिक तंगी और नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत के चलते उन्होंने यह साजिश रची। गिरोह का सदस्य विश्वजीत साहू 2डी और 3डी डिजाइनिंग का काम जानता था। जिसे उसने यूट्यूब और कोचिंग से सीखा था। पुलिस के मुताबिक,आरोपी पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी फर्जी टिकट बेचने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वहां सफल नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने तकनीक और डिजाइन में सुधार कर लखनऊ को निशाना बनाया।

लखनऊ पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए चारों आरोपियों में से एक नूतन डिप्लोमा होल्डर है, जबकि दूसरा विश्वजीत इंटर पास है। यूट्यूब से इन्होंने फर्जी टिकट बनाने और डिजाइन का काम, 2/3 डी डिजाइनिंग एलिवेशन सीखा है। श्रीकांत बोरकर ग्रेजुएट है। फर्जी टिकट बनाने वाले इस गिरोह का वो मास्टर माइंड है। डिजाइन के अलावा वो कार वॉशिंग का काम करता है। चौथा और मुख्य सहयोगी राजेंद्र चौधरी भी वाशिंग का काम करता है। डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद ने बताया कि, आरोपियों ने पीड़ित से 1000 यूपीआई के जरिए लिए थे। जिसके आधार पर पुलिस ने ट्रांजैक्शन ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और अन्य संभावित मामलों की जांच कर रही है।

आरोपियों से बरामद हुए सामान

15 फर्जी आईपीएल टिकट, 14 प्रिंटेड टिकट शीट, आशुश का लैपटॉप, 4 स्मार्ट मोबाइल फोन, पेपर कटर और प्रिंटिंग सामग्री, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड, सीजी नंबर की रिट्ज कार।

पांच राज्यों के बाद इंडिया गठबंधन की खुली कलई

सौरभ वार्ष्णेय

देश की राजनीति में विपक्षी एकता के बड़े दावे के साथ बना इंडिया गठबंधन अब लगातार अंतर्विरोधों और नेतृत्व संकट से जूझता दिखाई दे रहा है। जिस गठबंधन को लोकतंत्र बचाने और सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, वही आज आपसी अविश्वास, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और विचारधारात्मक टकराव का शिकार बनता जा रहा है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल सत्ता विरोध की राजनीति किसी गठबंधन को लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकती। वहीं बड़े स्तर पर आपसी बैठक व अपने मनमुटाव दूर कर गठबंधन का धर्म निभायें नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि यह विपक्षी राज्यस्तर वार धीरे धीरे अपनी भूमि भी खो बैठेंगे ? इंडिया गठबंधन का पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कहा जाता है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 2023 को इस उद्देश्य के साथ की गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ एकजुट होकर हराना है ताकि सत्ता हासिल की जा सकें जिसमें कुछ हद तक 240 तक रोकने में सफल हुए। इस गठबंधन में लगभग 30 विपक्षी दल थे। लोकसभा के बाद राज्यों में यही विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में मसगूल होकर जीतने चले थे लेकिन मिला क्या ? विपक्षी पार्टी के मुख्य चेहरे जो पार्टियां के मुख्य भी हैं वह अपने दल को भी हरा बैठे और यहां तक की खुद भी हार गये। यानि हारने के बाद फिर इंडिया गठबंधन की याद आने लगी। गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्पष्ट नेतृत्व न होना है। अलग-अलग राज्यों में दलों की अपनी-अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। बंगाल में अपनी राजनीति को प्राथमिकता देती हैं, तो दिल्ली और पंजाब के समीकरणों को लेकर अलग रणनीति अपनाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी सहयोगी दलों में पूर्ण सहमति दिखाई नहीं देती। परिणामस्वरूप गठबंधन का साझा एजेंडा लगातार धुंधला पड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पैदा होने वाले विवादों ने भी गठबंधन की कमजोरी उजागर कर दी है। कई राज्यों में सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। इससे जनता के बीच यह संदेश गया कि गठबंधन केवल चुनावी मजबूरी का प्रयोग है, न कि किसी वैचारिक प्रतिबद्धता का मंच। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक होता है, लेकिन विपक्ष तभी प्रभावी बन सकता है जब उसमें स्थिरता, स्पष्ट नीति और भरोसा हो। जनता अब केवल सरकार विरोधी नारों से संतुष्ट नहीं होती। देश के मतदाता रोजगार, महंगाई, विकास, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस दृष्टिकोण चाहते हैं। यदि विपक्ष इन मुद्दों पर एकजुट होकर विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो उसकी राजनीतिक स्वीकार्यता सीमित रह जाएगी। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त बैठकें और सोशल मीडिया अभियान किसी गठबंधन को जनआंदोलन का स्वरूप नहीं दे सकते। आज आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष आत्ममंथन करे। यदि इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी दल वास्तव में लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर साझा राष्ट्रीय दृष्टि प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा इंडिया गठबंधन की खुली कलई आने वाले समय में उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता को और कमजोर कर सकती है।

बंगाल में मोदी के साष्टांग दंडवत के निहितार्थ

मनोज कुमार अग्रवाल

पीएम नरेंद्र मोदी हर बार कुछ नया करते हैं पहलीबार जब संसद की दहलीज पर शीश नमन किया तो उसकी आवाज़ दूर तक गयी इस बार तो मोदी बंगाल की जीत और शपथ ग्रहण समारोह में उमड़े जन सैलाब को देख इतना आह्लादित हुए कि मंच पर ही साष्टांग दंडवत कर जनता जनार्दन के दिल में गहराई तक हिलोरें चला गए। कुछ भी कहो मोदी के घोर आलोचक भी मोदी के करिश्माई नेता होने से इंकार नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें भारतीय राजनीति के इतिहास में साल 2014 एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज है, जिसने न केवल केंद्र की सत्ता बदली, बल्कि राज्यों के राजनीतिक नक्शे को भी पूरी तरह से नई परिभाषा दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई है, जहां कभी पार्टी का अस्तित्व नगण्य माना जाता था। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने इस सफर को एक नई ऊंचाई दी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के अभेद्य शासन को समाप्त कर भाजपा ने बंगाल की सत्ता हासिल की है। यह केवल एक राज्य की जीत नहीं है, बल्कि उस लंबी यात्रा का शिखर है, जिसमें भाजपा ने पिछले 12 वर्षों में नौ ऐसे राज्यों में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया है, जहां पहले कभी उसका नेतृत्व नहीं रहा था भाजपा के इस स्वर्णिम काल की नींव 2014 में ही पड़ गई थी। हरियाणा, जिसे पारंपरिक रूप से लाल तिकड़ी और क्षेत्रीय क्षत्रपों का गढ़ माना जाता था, वहां भाजपा ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।साल 2016 भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जब पार्टी ने पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार असम में अपनी पहली सरकार बनाई। सर्बानंद सोनोवाल राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। असम की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा के लिए रास्ते खोल दिए।असम के बाद अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने एक अलग रणनीति के तहत सत्ता हासिल की। 2016 में बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच पेमा खांडू ने कांग्रेस छोड़ी और अंतत: अपने सहयोगियों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इससे राज्य में भाजपा की पहली स्थिर सरकार बनी। इसी तरह 2017 में मणिपुर में भी भाजपा ने क्षेत्रीय दलों जैसे नेशनल पीपुल्स पार्टी और



नगा पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बनाई।बिहार की राजनीति में भाजपा हमेशा से एक प्रमुख खिलाड़ी रही है, लेकिन वह लंबे समय तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारों में कनिष्ठ सहयोगी की भूमिका में रही। दो दशकों के इंतजार के बाद 2026 में वह क्षण आया जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद भाजपा ने अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया। पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा की अब तक की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर भाजपा ने उस राज्य में सरकार बनाई है, जो वैचारिक रूप से पार्टी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था।

परिवर्तनकारी नेता सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि उस लंबे राजनीतिक संघर्ष की परिणति है, जिसने बंगाल की जनता के भीतर परिवर्तन, सुशासन और विकास की उम्मीद को मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह क्षण ऐतिहासिक इसलिए भी है, क्योंकि बंगाल को पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री मिला है। आजादी के बाद से यह राज्य कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के शासन का साथी रहा, लेकिन अब राज्य की राजनीति में एक नया रंग, नई दिशा और नया विमर्श सामने आया है। भाजपा की जीत को पार्टी सोनार बांग्ला के संकल्प की शुरुआत के रूप में देख रही है। साथ ही सुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना भी अपने आप में बंगाल की राजनीति की असाधारण कहानी है। नगरपालिका के एक पार्षद से शुरू हुआ उनका सफर विधायक, सांसद, मंत्री, विपक्ष के नेता और अब मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। यह यात्रा केवल पदों की सीढ़ी चढ़ने की कहानी नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े राजनीतिक संघर्ष, संगठन क्षमता और जनाधार का प्रमाण है। पूर्वी मिदनापुर की गलियों से राज्य सत्ता के केंद्र तक पहुंचना उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को अलग पहचान देता है। नंदीग्राम आंदोलन ने सुवेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति में निर्णायक चेहरा बनाया। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए उस आंदोलन ने न केवल वाम मोर्चा सरक सरकार की जड़ों को हिलाया, बल्कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की पहली बड़ी पृष्ठभूमि भो तैयार की। सुवेंदु उस आंदोलन में एक ऐसे संगठक के रूप में उभरे, जो जनता की स्थानीय पीड़ा को राजनीतिक शक्ति में बदलना जानते थे। यही कारण है कि उनका नेतृत्व केवल चुनावी रणनीति का परिणाम नहीं माना जा सकता, बल्कि संघर्ष से निकले नेतृत्व की श्रेणी में रखा जा सकता है। 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर सुवेंदु अधिकारी ने अपनी राजनीतिक पहचान को और मजबूत किया। उस चुनाव में भाजपा भले सत्ता तक नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन नंदीग्राम की जीत ने पार्टी को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने तृणमूल सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक भूमिका निभाई और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक दृढ़ नेता की छवि बनाई। यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम स्वाभाविक रूप से सबसे आगे माना गया। भाजपा विधायक दल में उनके नाम पर सर्वसम्मति भी यह बताती है कि पार्टी अब बंगाल में नेतृत्व को लेकर स्पष्टता चाहती है। लंबे समय तक भाजपा को बंगाल में बाहरी शक्ति के रूप में प्रचारित किया जाता रहा, लेकिन सुर्वेद अधिकारी जैसे स्थानीय और जमीनी नेता के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा ने इस धारणा को चुनौती दी है। वे बंगाल की भाषा, मिट्टी, संघर्ष और सामाजिक मनोविज्ञान को समझने वाले नेता हैं। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। मिदनापुर से मुख्यमंत्री बनना भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। बंगाल की सत्ता लंबे समय तक कोलकाता केंद्रित राजनीतिक अभिजात वर्ग के इर्द-गिर्द घूमती रही। अधिकारी का उभार इस व्यवस्था से बाहर के क्षेत्रीय नेतृत्व की स्वीकृति है। मिदनापुर में जश्न का माहौल केवल राजनीतिक खुशी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति भी है। लोगों को उम्मीद है कि अब राज्य के उपेक्षित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में अधिक महत्व मिलेगा। अब सबसे बड़ी चुनौती भाजपा और सुर्वेद सरकार के सामने चुनावी वादों को प्रशासनिक परिणामों में बदलने की है। डबल इंजन सरकार का नारा जनता को तभी सार्थक लगेगा, जब राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल से रोजगार, उद्योग, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर ठोस बदलाव दिखेगा। बंगाल में राजनीतिक हिंसा लंबे समय से गंभीर चिंता का विषय रही है। नई सरकार के लिए पहली कसौटी यही होगी कि वह भयमुक्त राजनीतिक वातावरण बना सके। सबसे पहली चुनौती कानून-व्यवस्था की है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा, दलगत टकराव, सिंडिकेट संस्कृति और चुनावी हिंसा लंबे समय से गंभीर मुद्दे रहे हैं। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। अब जनता देखेगी कि नई सरकार अपराध और राजनीतिक संरक्षण के कथित गठजोड़ पर कितनी सख्ती दिखाती है। कानून का राज तभी स्थापित होगा जब कार्रवाई निष्पक्ष हो, चाहे आरोपी किसी भी दल, समूह या प्रभावशाली वर्ग से जुड़ा हो। दूसरी बड़ी चुनौती प्रशासनिक सुधार की है। बंगाल में वर्षों से सरकारी व्यवस्था पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। यदि नई सरकार सचमुच सुशासन का दावा करती है, तो उसे थाने, ब्लॉक कार्यालय, पंचायत व्यवस्था, नगर प्रशासन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लानी होगी।

भाजपा के सामने यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने राजनीतिक विस्तार को सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ जोड़े। बंगाल में यह क्रांतिकारी परिवर्तन सचमुच सोनार बांग्ला ही नही सोनार भारत की दिशा में मजबूत कदम है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक अत्यंत प्रभावशाली और क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने 12 वर्षों से अधिक के अपने कार्यकाल में बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से देश में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधान सेवक के रूप में, उन्होंने सीमा सुरक्षा, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर बड़े फैसले लेने और विकसित भारत के निर्माण में अपनी एक अलग पहचान बनाई है वहीं भाजपा को सत्ता के चरम शिखर पर पहुंचाने के संकल्प को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज समूचे देश में भगवा राजनीति छा चुकी है यह एक नए भविष्य का सूत्रपात करेगी।

पुराण दिग्दर्शन ....



सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

तद् दृष्ट्वा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः।
ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्।।2।।
एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी।
इयं च लक्ष्म्याः संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी।।3।।
पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः।।4।।
चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवापरुधन्ती।।5।।

(श्रीमद्भागवत 4 । 15)

अर्थात् (वेन के मर जाने पर उसके शरीर के मथने से जब निषाद उत्पन्न हो चुका) इसके पश्चात् पुत्रहीन राजा वेन के शरीर को ऋषियों ने फिर मथा तब उसकी भुजाओं से एक जोड़ा पैदा हुवा।।1।। ब्रह्मवादी ऋषि उत्पन्न हुवे उस मिथुन को भगवान् की कला जान कर प्रसन्न होकर बोले।।2।। इनमें जो पुरुष है वह भुवन की रक्षा करने वाली विष्णु की कला है, और जो स्त्री है, वह विष्णु भगवान् की अनन्य प्रिया लक्ष्मी की कला है॥ 3॥ सो यह पुरुष महान् यशस्वी पृथु राजा होगा॥4। और यह कन्या पृथु की अर्धा-ङ्गिनी चि नाम से विख्यात होगी।।5।।

उपर्युक्त पौराणिक-स्वरूप के मूल शब्दों से ही उक्त दोनों व्यक्तियों का भाई बहिन होना सिद्ध नहीं होता, किन्तु विष्णु और लक्ष्मी के कलावतार होने के कारण दोनों का पति-पत्नी होना ही सिद्ध होता है। कदाचित् शङ्कावादी महाशय वेन के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इन दोनों को भाई बहिन बताने का प्रयत्न करेगा तो उसे स्वयं भी इस आक्षेप का पात्र बनना पड़ेगा, क्योंकि महाशय जी और उनकी श्रीमती जी दोनों भी तो एक निराकार से ही सृष्टि के आरम्भ में टपक पड़े थे। अतः यही मानना पड़ेगा कि अयोनिज सृष्टि में तादृश सम्बन्ध नहीं माना जाता, किन्तु योनिज में ही एक दूसरे का वह सम्बन्ध युक्तिसंगत है। हम ब्रह्मा दुहिता प्रसंग में यह विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं यहाँ दुहराने को आवश्यकता नहीं। **क्रमशः ...**

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस

योगेश कुमार गोयल

दया और सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता माना जाता हैं, जिनकी इस वर्ष हम 206वीं जयंती मना रहे हैं। प्रतिवर्ष उन्हीं की जयंती को 12 मई को एक विशेष थीम के साथ 'अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस' के रूप में मनाया जाता है और इस विशेष अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के योगदान को नमन करना बेहद जरूरी है। इस वर्ष यह दिवस 'हमारी नर्सें। हमारा भविष्य। सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं।' थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस विषय का उद्देश्य सुरक्षित वातावरण, उचित वेतन और नेतृत्व के अवसरों के माध्यम से नर्सों को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि रोगी देखभाल और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया जा सके। 'लेडी



विद द लैंप' के नाम से विख्यात नाइटिंगेल का जन्म 206 वर्ष पहले 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में नर्सों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए उन्हीं के नाम से 'फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार' की स्थापना की गई थी, जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बेहद खूबसूरत, पढ़ी-लिखी और समझदार युवती थी। उन्होंने अंग्रेजी, इटेलियन, लैटिन, जर्मनी, फ्रैंच, इतिहास और दर्शन शास्त्र सीखा था तथा अपनी बहन और माता-पिता के साथ कई देशों की यात्रा की थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उन्हें अहसास हो गया था कि उनका जन्म सेवा कार्यों के लिए ही हुआ है। हालांकि उस दौर में नर्सिंग को एक सम्मानित व्यवसाय भी नहीं माना जाता था, इसलिए उनके माता-पिता का मानना था कि धनी परिवार की लड़की के लिए वह पेशा सही नहीं है। दरअसल वह ऐसा समय था, जब अस्पताल बेहद गंदी जगह पर होते थे और वहां बीमार लोगों की मौत के बाद काफी भयावह माहौल हो जाता था। 1850 में फ्लोरेंस ने जर्मनी में प्रोटेस्टेंट डेकोनेसिस संस्थान में दो सप्ताह की अवधि में एक नर्स के रूप में अपना प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूरा किया। मरीजों, गरीबों और पीड़ितों के प्रति उनके सेवाभाव को देखते हुए आखिरकार उनके माता-पिता द्वारा वर्ष 1851 में उन्हें नर्सिंग की आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी में महिलाओं के लिए एक क्रिश्चियन स्कूल में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने मरीजों की देखभाल के तरीकों और अस्पतालों को साफ रखने के महत्व के बारे में जाना।

ब्रिटिश सरकार द्वारा फ्लोरेंस के नेतृत्व में अक्तूबर 1854 में 38 नर्सों का एक दल घायल सैनिकों की सेवा के लिए तुर्की भेजा गया। फ्लोरेंस ने वहां पहुंचकर देखा कि किस प्रकार वहां अस्पताल घायल सैनिकों से खचाखच भरे हुए थे, जहां गंदगी, दुर्गंध, दवाओं तथा उपकरणों की कमी, दूषित पेयजल इत्यादि के कारण असुविधाओं के बीच संक्रमण से सैनिकों की बड़ी संख्या में मौतें हो रही थी।

क्या अब मुस्लिम वोट अपनी अहमियत खो रहा है?

शेखर गुप्ता

करीब सात वर्ष पहले मैंने आलेख लिखा था जिसका शीर्षक था-'क्या भारतीय मुस्लिम अहमियत रखते हैं?' उस सवाल को दोबारा उठाने का यह सही समय है।

हालिया विधान सभा चुनावों के नतीजे, खासकर पश्चिम बंगाल और असम के जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 30 फीसदी से ज्यादा है, दिखाते हैं कि यह मुद्दा अब भी मौजूद है बल्कि शायद और बड़ा हो गया है। जवाब कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं। राजनीतिक नजरिये से निष्कर्ष यह होगा कि मोदी-शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए आज मुसलमानों की अहमियत 2019 से भी कम है।

पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा ने इस बार एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया मगर दो तिहाई सीटों पर जीत हासिल कर ली। लेकिन असम में विपक्ष को देखें तो जीतने वाले 24 उम्मीदवारों में से 22 मुसलमान हैं। इसमें 18 कांग्रेस के हैं, जिसने कुल 19 मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए थे।

पश्चिम बंगाल में 293 नवनिर्वाचित विधायकों में से 40 मुसलमान हैं। इनमें से 34 तृणमूल कांग्रेस से हैं और पार्टी द्वारा जीती कुल 80 सीटों में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। इस तरह मुसलनाम उन दो राज्यों में (जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है) सत्ता व्यवस्था से बाहर हैं, जहां उनकी सबसे बड़ी आबादी है। वे पूरी तरह हाशिये पर धकेल दिए गए हैं और भाजपा के इकलौते विपक्ष बनकर रह गए हैं। विडंबना या विरोधाभास यह है कि उनके नेता अब भी हिंदू हैं और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में वे सभी हार गए हैं।

इन चुनावों ने भाजपा और धर्मनिरपेक्ष दलों के अंतर को पूरी तरह हिंदू और मुसलमान का अंतर बना दिया है। उदाहरण के लिए केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 102 नवनिर्वाचित विधायकों में से 30 मुसलमान और 29 ईसाई हैं। धर्मनिरपेक्ष दलों को इस बात से राहत है कि कम से कम केरल में



मुसलमानों को जगह मिली हुई है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि भाजपा अब इसे अल्पसंख्यक शासन का प्रमाण बताकर हिंदू वोट एकजुट करेगी और केरल के ईसाइयों को विभाजित करने की कोशिश करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 18वीं लोकसभा में 24 यानी केवल 4.42 प्रतिशत सांसद मुसलमान हैं, जबकि राष्ट्रीय मतदाता सूची में 15 प्रतिशत से ज्यादा मुसलमान शामिल हैं। 16वीं लोकसभा में 22 और 17वीं लोकसभा में 27 मुसलमान सांसद थे। हालांकि यह बात उतनी हैरान करने वाली नहीं है, जितनी पहली नजर में करती है। मुसलमानों ने 1980 में 49 यानी 9 प्रतिशत और 1984 में 45 यानी 8.3 प्रतिशत सीट जीती थीं। इन दो मौकों को छोड़ दें तो लोकसभा में मुसलमान सांसद 5 प्रतिशत के आसपास ही रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें हमेशा अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। यहां तक कि वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भी सिकंदर बख्त थे।

मुसलमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर और कई दफा तो सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के मुखिया जैसे पदों पर भी रहते थे। आज ऐसा नहीं है। देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है, जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है। केवल बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन मुस्लिम राज्यपाल हैं। केंद्र सरकार के करीब 100 सचिवों में कामरान रिजवी (भारी उद्योग) इकलौते मुसलमान हैं। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के 32 न्यायाधीशों में अभी इकलौते मुसलमान न्यायाधीश हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले अंतिम मुसलमान न्यायमूर्ति एएम अहमदी थे, जो 24 मार्च 1997 को सेवानिवृत्त हुए थे।

इस सूची से भले ही ऐसा लगता हो कि भारत में मुसलमानों को हाशिये पर धकेला जा रहा है लेकिन इस पर पुनर्विचार करना होगा। बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान चिकित्सा, विधि, शिक्षा, विज्ञान, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और मनोरंजन या समाचार जगत में प्रवेश कर रहे हैं। सिविल सेवा और सशस्त्र बलों (ऑफिसर्स अकादमी सहित) में मुसलमानों का चयन बढ़ रहा है। इसलिए हकीकत यही है कि प्रतिनिधित्व केवल राजनीति में कम हो रहा है।

2019 में मैंने अपने पहले स्तंभ का शीर्षक भाजपा नेता, बौद्धिक/विचारक प्रवक्ता और पूर्व राज्य सभा सांसद बलबीर पुंज के साथ 1999 में हुई एक बातचीत से लिया था। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस समूह में कुछ समय तक मेरे साथ काम भी किया था। वह द फाइनैंशियल एक्सप्रेस के लिए लिखा करते थे। पुंज का गत माह निधन हो गया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली दूसरी सरकार के एक वोट से गिर जाने पर वह बहुत नाराज थे। इससे पहले 1996 में वाजपेयी की सरकार 13 दिन चली थी।

वह इस बात से हताश थे कि मुस्लिम मतों के भरोसे रहने वाला कोई दल भाजपा को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस तरह मुसलमान ही तय कर रहे थे कि भारत पर किसका शासन होगा। मोदी-शाह के दौर में सब कुछ बदल गया।

ये तथ्य तीन अहम नतीजों की ओर संकेत करते हैं-

1. भाजपा के प्रतिद्वंद्वी या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल बहुत हद तक मुसलमानों की पार्टी लगने लगे हैं, जबकि उनके नेता हिंदू हैं। भाजपा भी यही चाहती है। 80 फीसदी हिंदू और 20 फीसदी अन्य के साथ हिंदू बनाम अन्य का यह समीकरण उसके पक्ष में जाता है। वे चुनिंदा इलाकों में ईसाइयों पर काम करना जारी रखेंगे। पार्टी गोवा में जीत चुकी है और केरल में शुरुआत हो चुकी है। भाजपा के पास धैर्य और समय है। पूर्वोत्तर में उसने ईसाई जनजातियों के साथ सहज रिश्ता कायम किया है। भाजपा ने इनमें से किसी भी राज्य में बीफ पर प्रतिबंध की मांग नहीं की है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी इसे पाखंड बताते हुए ताना कसते हैं, 'यूपी की गाय मम्मी, नॉर्थईस्ट में गाय यम्मी।' कुछ धर्मनिरपेक्ष दल अब भी मुसलमानों के वोट पर निर्भर हैं, लेकिन वे मुसलमानों के समर्थन में खुलकर बोलने से भी बचते हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने शाहीन बाग आंदोलन और उसके बाद हुए दंगों के दौरान चुप्पी बनाए रखी। मुस्लिम समर्थक कहलाने के भय ने ही उन्हें दूर रखा।

2. ऐसे में भारतीय धर्मनिरपेक्षता को बचाने का बोझ मुसलमानों पर ही आ जाता है। यह मुश्किल और अव्यावहारिक तो है ही गलत भी है। मुसलमान समुदाय बंटा हुआ है और अहम चुनावी क्षेत्रों में उसके पास बहुमत नहीं है। आज उनसे कहा जा रहा है कि उस उम्मीदवार को वोट दें जिसके भाजपा को हराने की सबसे अधिक उम्मीद है ताकि उनका बचाव हो सके।

3. ओवैसी ने एक और विचार दिया है- मुसलमान अपने राजनीतिक दल बनाएं और अपने नेता चुनें। यह विचार टिकाऊ नहीं है क्योंकि पूरा भारत पुराना हैदराबाद नहीं है। अगर मुस्लिम अपने राजनीतिक दल बना लेते हैं तो उनसे भाजपा की ताकत ही कई गुना बढ़ेगी। सच तो यह है कि जिन्ना के बाद भारतीय मुसलमानों ने कभी किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। चाहे नेहरू-गांधी परिवार हो या उत्तर प्रदेश तथा बिहार में यादव और दूसरी जगहों पर वाम एवं ममता बनर्जी, मुसलमानों ने हिंदू नेताओं पर भरोसा किया। पता नहीं यह उनके कितने काम आया लेकिन वे सत्ता संरचना से इतने बाहर कभी नहीं थे जितने आज हैं।

आज का इतिहास

1881 आक्रमण के खतरे के तहत, ट्यूनीस मुहम्मद तिसिया-सादिक की बे ने ट्यूनीशिया को फ्रेंचप्रोटेक्टोरेट बनाने के लिए बार्डो की संधि पर हस्ताक्षर किए।
1885 सस्काचेवान की अनंतिम सरकार को बटोच की लड़ाई में निर्णायक रूप से हटा दिया गया था, जिसके कारण तीन दिन बाद उत्तर-पश्चिम विद्रोह समाप्त हो गया था।
1902 पेंसिल्वेनिया में एन्थ्रेसाइट कोयला के एक लाख 40 हजार श्रमिकों ने हड़ताल की।
1921 पहला नेशनल हॉस्पिटल डे मनाया गया।
1926 इटालियन निर्मित अर्ध-कठोर एयरशिप नॉरगे ने 12 मई, 1926 को उत्तरी ध्रुव का पहला सत्यापित ओवरफ्लाइट पूरा किया। यह यूरोप और अमेरिका के बीच ध्रुवीय बर्फ की टोपी पर उड़ान भरने वाला पहला हवाई पोत भी था।
1926 ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, ब्रिटिश व्यापारों के एक संघ, ने घोषणा की कि वह अपनी सप्ताह भर की सामान्य हड़ताल [कोयला] खनिकों की मजदूरी और घंटों की अनिश्चितता को समाप्त करेगी।
1926 रोआल्डअमुनडसेन के नेतृत्व में हवाई पोत नॉरज के चालक दल, नॉर्थपोल के लिए एक सत्यापित यात्रा करने वाले पहले लोग बन गए।
1926 हवाई पोत नोर्गे उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाला पहला पोत बना।
1932 विल्हेम ग्रोनर ने जर्मनी के रक्षामंत्री के पद से इस्तीफा दिया।
1942 द्वितीय विश्वयुद्ध-सोवियत सेनाओं के तहत मार्शल शिमशोन टिमोसेनकोला ने पूर्वी यूक्रेन में एक बड़े हमले को अंजाम दिया, केवल दो सप्ताह बाद जर्मन सैनिकों द्वारा नष्ट किए गए घेरने के लिए।
1942 खारकोव की दूसरी लड़ाई शुरू हुई।
1955 ऑस्ट्रिया ने 12 मई, 1955 को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी यह 1945 से 1955 तक मित्र देशों के कब्जे में रहा। ऑस्ट्रिया राज्य नाजी आक्रमण का पहला शिकार था और राष्ट्रीय समाजवादी की इस विवादास्पद विदेश नीति को इतिहास में विक्टिम थ्योरी कहा जाता है।
1958 कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तरी अमेरिका के लिए एयरोस्पेसेश्वरिंग और रक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर अमेरिकी वायु रक्षा कमान के एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1965 पश्चिम जर्मनी और इज़राइल राजनयिक संबंध स्थापित किये।

तामिलनाडु के द्रविड़ राजनीति में विजय का उदय

राज कुमार सिन्हा

वर्तमान तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव आया है। दशकों से चले आ रहे द्रविड़ राजनीति के दो पार्टियां द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (एआईएडीएमके) के वर्चस्व को पीछे छोडते हुए अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कडगम (टीवीके) ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 107 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी जगह बनाई है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने तमिलगा वेट्री कडगम (टीवीके) पार्टी के अध्यक्ष जोसेफ विजय द्वारा सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया था। जबकि टीवीके के संस्थापक जोसेफ विजय राज्यपाल अर्लेकर से दो बार मुलाकात कर सरकार बनाने का निमंत्रण देने का अनुरोध किया था। जोसेफ विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में राज्यपाल की देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई।यह सर्वविदित है कि संविधान द्वारा शासित संसदीय लोकतंत्र में, किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त है या नहीं, यह प्रश्न केवल सदन के पटल पर ही निर्धारित किया जा सकता है।

दूसरी ओर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच वार्ता और एडप्पाडी पलानीस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनाने के प्रयासों की खबरें भी आई जो जनादेश के विरुद्ध था। तमिलनाडु में अंदरखाने राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा होने लगा था। तमिलनाडु में विजय की सरकार को कांग्रेस, लेफ्ट और वीसीके ने अपना समर्थन दिया है। आईयूएमएल ने भी टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है।तामिलनाडु में सरकार गठन के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए था जो अब 121 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इसके बाद टीवीके की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस चुनाव में विजय ने दो विधानसभा सीटों से जीत हासिल की है। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन उसके बाद भी सरकार बनाने को लेकर जोसेफ विजय को काफी दिक्कतें आई हैं। हालांकि, मुश्किलों को हल करने में राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम रही है। तमिलनाडु में टीवीके चीफ विजय रविवार को राज्य के 9 वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है।इनके साथ नौ लोगों ने मंत्री पद का शपथ लिया है।जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके का उदय तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। यह केवल एक फिल्म अभिनेता के राजनीति में आने की घटना नहीं है, बल्कि राज्य की बदलती सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों, युवाओं की अपेक्षाओं और द्रविड़ राजनीति के भीतर उभरते खाली स्थान का परिणाम भी है।विजय



तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में से हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार विरोध और युवा शक्ति जैसे मुद्दे दिखाए जाते रहे हैं। उनका प्रशंसक नेटवर्क वर्षों से संगठित रूप में काम कर रहा था, जो अब राजनीतिक ढांचे में बदला गया है।टीवीके ने अभी तक खुद को पूरी तरह किसी एक वैचारिक ध्रुव से नहीं जोड़ा है।वे द्रविड़ पहचान, सामाजिक न्याय और तमिल अस्मिता को बनाए रखते हुए सर्वसमावेशी छवि बनाना चाहते हैं।वे युवाओं को रोजगार, पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन पर जोर देकर नई पीढ़ी को द्रविड़ राजनीति में जोडा है। इस बार के चुनाव में एआईएडीएमके का वोट शेयर लगभग 12 प्रतिशत तक गिरा है। इस बार सिर्फ पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, बल्कि वह मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी गंवा बैठी है।

डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पार्टियां पेरियार और अन्नादुरई के सिद्धांतों जैसे सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, हिंदी विरोध को मानती है।1967 से तमिलनाडु में केवल इन दो पार्टियों ने ही सरकारें बनाई हैं, जो बारी-बारी से सत्ता में आती रही हैं। दोनों ही पार्टियों का फिल्मी जगत से गहरा संबंध रहा है, जहां नेता अक्सर पटकथा लेखक या अभिनेता रहे हैं।डीएमके का उदय 1949 में हुआ था।सी.एन. अन्नादुरई ने पेरियार के कुछ विचारों से असहमति के बाद डीएमके बनाई, जो चुनावी राजनीति में उतरी। दक्षिण के बडे अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन ने करुणानिधि से विवाद के बाद डीएमके से अलग होकर 1972 में एआईएडीएमके बनाई।बाद में जयललिता ने इस पार्टी की कमान संभाली थी। जयललिता भी दक्षिण की मशहूर अभिनेत्री थी। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति का इतिहास 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना से शुरू होकर आज की डीएमके और एआईएडीएमके के बीच वैचारिक और सत्ता संघर्ष का 110 साल पुराना सफर है।जस्टिस पार्टी की शुरुआत गैर-ब्राह्मण आंदोलन से हुई, जो प्रशासन और शिक्षा में ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ था।बाद में जस्टिस पार्टी को पेरियार ई.वी. रामासामी ने द्रविड़ कड़गम में बदला, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र द्रविड़ नाडु और सामाजिक सुधार था।तमिलनाडु की राजनीति देश के बाकी राज्यों से काफी अलग मानी जाती है। ऐसा इसलिए कि यहां जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक न्याय की राजनीति ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे द्रविड़ राजनीति कहा जाता है। राज्य की दो सबसे बड़ी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके एक ही द्रविड़ आंदोलन से निकली है, दोनों की विचारधारा लगभग समान है, लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों दशकों से कट्टर प्रतिद्वंद्वी बनी हुई है और पिछले पांच दशक से ज्यादा समय से तमिल राजनीति पर कब्जा किया हुआ है। 1967 का विधानसभा चुनाव तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, जहां डीएमके ने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल कर ली और सी. एन. अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था जब किसी क्षेत्रीय दल ने राज्य में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति लगभग पूरी तरह द्रविड़ दलों के नियंत्रण में आ गई। अन्नादुरई की मृत्यु के बाद एम. करुणानिधि डीएमके के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे।1969 में सी.एन. अन्नादुरई के निधन के बाद, कलाइग्नार एम. करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और पांच बार इस पद पर आसीन हुए। उन्होंने 2016 तक हुए सभी 13 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया। 2018 में, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण, डीएमके की आम सभा की बैठक हुई और एम.के. स्टालिन को डीएमके को अध्यक्ष चुना गया था।1980 और 1990 के दशक में तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह करुणानिधि बनाम जयललिता में बदल गई। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक संघर्ष बेहद तीखा था। विधानसभा से लेकर सड़कों तक टकराव दिखाई देता था।

तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी लोकप्रियता महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल स्टारडम से सत्ता नहीं मिलती।एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता सफल हुए क्योंकि उन्होंने मजबूत संगठन और जनकल्याणकारी राजनीति भी विकसित की थी। नई पार्टियों पर अक्सर आरोप लगता है कि वे केवल एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द बनी हैं। यदि टीवीके अलग-अलग चेहरों को आगे करती है, तो वह खुद को संगठन आधारित पार्टी के रूप में पेश कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है।यदि विजय किसी विशेष समुदाय से जुड़े माने जाते हैं, तो पार्टी दूसरे समुदाय और धर्म के चेहरे को आगे कर व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना चाहिए। विजय की लोकप्रियता और उसकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह पार्टी को मजबूत संगठन, स्पष्ट नीतियां और विश्वसनीय राजनीतिक नेतृत्व कितना विकसित कर पाते हैं।

राहुल गांधी का संगठनात्मक सुधारों व मजबूत जमीनी जुड़ाव पर जोर

राहिल नोरा चोपड़ा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने धर्मशाला में जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए संगठनात्मक सुधारों और मजबूत जमीनी जुड़ाव पर जोर दिया। 'संगठन सृजन अभियान' के तहत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य पार्टी की जमीनी स्तर की संरचना को मजबूत करना था और इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 62 पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में संगठनात्मक मुद्दों, नीतिगत चुनौतियों और जमीनी स्तर पर पहुंच बनाने पर चर्चा शामिल थी। राहुल गांधी की यात्रा महिला प्रतिनिधित्व के विस्तार पर आंतरिक चर्चाओं के साथ भी मेल खाती थी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस विधानसभाओं में और पार्टी की संरचना के भीतर महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण के लिए दबाव बना रही है और भाजपा पर इसके कार्यान्वयन में देरी करने का आरोप लगा रही है। केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए आई.यू.एम.एल. की भूमिका अहम = यूनाइटेड डैमोक्रेटिक फ्रंट (यू.डी.एफ.) के लिए सत्ता में संभावित वापसी का पूर्वानुमान लगाने वाले एग्जिट पोल के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यू.डी.एफ. के दूसरे सबसे बड़े घटक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आई.यू.एम.एल.) ने मुख्यमंत्री पद के लिए वी.डी. सतीशन के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। आई.यू.एम.एल. केरल के अध्यक्ष सादिक अली शिहाब थंगल ने कहा कि एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री पद के लिए वी.डी. सतीशन को मिला समर्थन जनता की भावना है। यह संकेत देता है कि यह लोगों की राय है। सतीशन के लिए आई.यू.एम.एल. का खुला समर्थन कांग्रेस के कुछ खास वर्गों के भीतर समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि, पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि कांग्रेस आलाकमान घटनाक्रम से अवगत है और स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। इस बीच, यू.डी.एफ. में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, केरल कांग्रेस (जोसेफ) ने मुख्यमंत्री चयन को लेकर चल रही बहस में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और कहा कि अगले मुख्यमंत्री का मुद्दा कांग्रेस का आंतरिक मामला है। जबकि सबसे वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला भी एक मजबूत दावेदार हैं। चेन्नीथला सोनिया गांधी के करीबी हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान निर्वाचित विधायकों के विचारों पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर अंतिम निर्णय लेता है लेकिन 140 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के संकीर्ण अंतर से जीतने पर यू.डी.एफ. की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आई.यू.एम.एल. की भूमिका निर्णायक होगी। कर्नाटक में जारी नेतृत्व परिवर्तन का संकट: कर्नाटक कांग्रेस में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की चल रही फुसफुसाहट के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री को बदलने की कोई योजना नहीं है और उम्मीद जताई कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के समर्थक उन्हें पदोन्नत करने पर जोर दे रहे हैं, यह सांझा करते हुए कि 2023 में कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ एक कथित शक्ति-सांझाकरण समझौता हुआ था। जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खेमा मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि डी.के. शिवकुमार, जो मुख्यमंत्री पद की ओर देख रहे हैं, इस फेरबदल के विरोधी हैं। वर्तमान में, के.एन. राजन्ना और बी. नागेंद्र के इस्तीफे के कारण 2 कैबिनेट पद खाली हैं। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे को सुलझाने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद सिद्धारमैया और शिवकुमार को बुलाने की इच्छा व्यक्त की है।

कैसे ममता से दूर हुए शुभेंदु अधिकारी?

आदिति फडणीस

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार में शुभेंदु अधिकारी के एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी के बीच ममता बनर्जी के कई समर्थकों को कुछ साल पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की कैबिनेट बैठक में हुई एक बातचीत को याद करना चाहिए। ममता ने अचानक हंगामा किया और उठकर बैठक से चली गईं। एक मंत्री ने झुंझलाकर कहा, 'ममता को क्या हो गया है!'

हालांकि मंत्री ने यह ऐसे ही बोल दिया था लेकिन वहां मौजूद प्रणव मुखर्जी ने इसका उत्तर देना उचित समझा। उन्होंने अपना चश्मा उतारा, उसे साफ किया, फिर से पहना और धीरे से कहा : 'अगर कोई यह सोचे कि वह रवींद्रनाथ ठाकुर से बेहतर कवि, बीथोवेन से बेहतर (संगीतकार) और लियोनार्दो दा विंची से बेहतर चित्रकार है, तो फिर उसके लिए सब कुछ एक समस्या है।'

यह ममता की ही अतिवादी सोच थी, और केवल उन्हीं की, जिसने शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से बाहर निकालकर भाजपा की गोद में धकेल दिया।

अधिकारी का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण बंगाल है। उनके पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेसी और प्रभावशाली नेता थे, जो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। वामपंथियों के वर्चस्व वाले कोंताई और तमलुक के इलाकों में,कांग्रेस का झंडा बुलंद था। वामपंथियों का साम्राज्य धीरे-धीरे ढहता गया, नंदीग्राम ने इसके पतन को और तेज कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ही वामपंथियों द्वारा 'भूमि हड़पने' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

उनकी क्षमता को पहचानते हुए, ममता ने उन्हें टीएमसी युवा शाखा का अध्यक्ष और उस समय माओवादी समूहों के प्रभाव में रहे जंगलमहल के लिए पार्टी का पर्यवेक्षक बनाया। पांच साल से भी कम समय में, टीएमसी कांग्रेस और वामपंथी दलों, दोनों से यह राजनीतिक क्षेत्र छीनने में सफल रही। साथ ही क्षेत्र के उन युवाओं का विश्वास भी पुन: प्राप्त करने में कामयाब रही जो वामपंथी उग्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे थे।



उनका उदय प्रभावशाली रहा। 2009 में, शुभेंदु तमलुक से लोक सभा के लिए चुने गए, उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ को 1,72,000 वोटों से हराया। वर्ष 2014 में उन्होंने माकपा के इब्राहिम अली को हराकर तमलुक संसदीय सीट बरकरार रखी।

टीएमसी ने 2016 में उन्हें नंदीग्राम विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला वाम मोर्चा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार अब्दुल कादिर शेख से था। शुभेंदु ने 67 फीसदी से अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। उनकी शानदार जीत के बाद ममता ने उन्हें परिवहन मंत्री बनाया। वर्ष 2018 में उन्हें पर्यावरण मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया। लेकिन ममता उनके बढ़ते प्रभाव से चिंतित होने लगीं।

इसके अलावा, उनकी अपनी उत्तराधिकार योजना थी जिसमें शुभेंदु का कोई स्थान नहीं था। लेकिन वह उनके सिद्ध राजनीतिक कार्यों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकीं, इसलिए एक समानांतर संगठन, टीएमसी युवा बनाया गया और उनके भतीजे अभिषेक को इसका प्रमुख चुना गया। बाद में उन्होंने टीएमसी युवा को भंग कर दिया और टीएमसी की युवा शाखा को पुनर्जीवित किया- एक बार फिर अभिषेक के नेतृत्व में। शुभेंदु का उपयोग पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया, लेकिन उन्हें ममता के करीबी लोगों में कभी शामिल नहीं किया गया।

वह भी दरबारी कहलाना पसंद नहीं करते थे। विधायक के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी कोलकाता में रात न बिताएं। वह प्रतिदिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से राज्य की राजधानी तक 200 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, कभी-कभी रात के 1 बजे घर पहुंचते थे और फिर सुबह जल्दी काम पर जाने के लिए निकल जाते थे।

मुख्यमंत्री और उनके सबसे महत्त्वपूर्ण मंत्री के बीच विश्वास की कमी स्पष्ट हो गई। उन्होंने एक बार कहा था, 'मैं परिवहन मंत्री था, लेकिन मंत्रालय ममता चला रही थीं।' अपमानों का सिलसिला बढ़ता ही गया। इन सबके मूल में 'शुभेंदु और अभिषेक के बीच की प्रतिद्वंद्विता थी। वर्ष 2020 में दुर्गा पूजा के दौरान तो ऐसा लगा मानो मतभेद सुलझ ही नहीं सकते। शुभेंदु के निर्वाचन क्षेत्र में उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में हर जगह पोस्टर लगे हुए थे जिन पर लिखा था- 'दादार अनुगामी (दादा का अनुयायी)।'

आधिकारिक तौर पर शुभेंदु ने इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। लेकिन इन कार्यक्रमों में टीएमसी का कोई बैनर या ममता की तस्वीर नहीं थी। इसी बीच, टीएमसी नेता नंदीग्राम गए और वहां एक बैठक की, जिसमें उन्हें 'मीर जाफर' कहकर संबोधित किया गया। उसी वर्ष के अंत में 2021 के विधान सभा चुनावों से पहले शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद, ममता की अपनी पार्टी पर ऐसी पकड़ थी कि नेताओं को पता था कि उन्हें उनकी हर जिद पूरी करनी होगी अन्यथा दरकिनार कर दिया जाएगा। इसके चलते कुछ ऐसे अप्रत्याशित परिणाम सामने आए कि कई नेताओं को, जो यह मानकर चल रहे थे कि उनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ममता द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद यह पता चला कि उन्हें आखिर क्यों बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उदाहरण के लिए, उन्हें दरकिनार किए जाने के कारणों में ममता के गाते समय रवींद्र संगीत को पूरी एकाग्रता के साथ न सुनना या ममता की बताई दवाएं न लेना (वह खुद को डॉक्टर समझती हैं) शामिल हैं।

अब जब ममता मुश्किल हालात में खड़ी हैं, तो उन्हें खुद का, उन सभी लोगों का जिन्हें उन्होंने खुद से दूर कर दिया है, गहराई से आकलन करने की जरूरत है और खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उनकी दुनिया उनके पैरों के पास ही खंडहर बनकर बिखर गई है।

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के निहितार्थ

राधा रमण

पिछले महीने पांच राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। चुनाव हमारे लोकतंत्र की परीक्षा होते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में मतदाताओं की ताकत सिर चढ़कर बोलता है। मतदाता जिसे चाहें अर्श से फर्स पर उतार देते हैं और जिसे चाहें फर्स से अर्श पर पहुंचा देते हैं। हर चुनाव में यही होते रहा है, आगे भी यही होता रहेगा। इस बार के चुनाव परिणाम भी इसी धारणा को मजबूती देते हैं।

तमिलनाडु में मतदाताओं ने 64 वर्ष बाद किसी नई पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश दिया है। वहां पिछले 64 वर्षों में कभी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईडीएमके) तो कभी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को सरकार बनाने का मौका मिलता रहता था। इसमें दो राय नहीं कि वहां की जनता दोनों की सरकारें और उनकी अदला-बदली से तंग आ चुकी थी। इसीलिए उसने इस बार पहली बार चुनाव मैदान में उतरे तमिल फिल्मों के सुपर हीरो जोसेफ विजय की नई नवेली पार्टी तमिलागा वेत्रि कड़गम (टीवीके) की झोली में 234 सदस्यीय विधानसभा में 107 सीटें डाल दी। वहां डीएमके गठबंधन को 74 और एआईडीएमके गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं। अब विजय दोनों ही गठबंधनों से कुछ विधायकों को तोड़कर आसानी से सरकार बना सकते हैं। इसमें दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि दोनों ही दलों ने अपने गठबंधन में शामिल दलों को सरकार में भागीदारी नहीं दी थी।

पश्चिम बंगाल में पहली बार 206 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाने के लिए तैयारी में है। वहां पिछली बार 215 सीटों पर जीत के साथ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी। इस बार के चुनाव में तृणमूल कांगेस महज 81 सीटों पर सिमट गई है और ममता बनर्जी स्वयं चुनाव हार चुकी हैं। उन्होंने मतगणना केंद्र में सीसीटीवी बंद कर अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। पिछले चुनाव में भाजपा को 77 सीटें मिली थीं। इस बार उसे 129 सीटों का फायदा हुआ है। भाजपा के वोटों में यह उछाल



अचानक नहीं आया है। इसके लिए भाजपा के देशभर के कार्यकर्ता लगातार पांच वर्षों तक राज्य में डेरा डाले रहे। उन्होंने घर-घर जाकर मतदाताओं का मन टटोला। उन्हें अपने साथ आने को प्रेरित किया। साम-दाम-दंड-भेद के घोड़े छोड़ डाले। एक हुमायूं कबीर से डील की बातें तो सार्वजनिक भी हो गईं। हालांकि बाद में भाजपा और हुमायूं कबीर दोनों ने इसका खंडन किया। लेकिन अगर दोनों सही थे तो असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्यों बिदक गए, यह सवाल अनुत्तरित ही रहा।

वैसे भी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के पीछे सत्ता विरोधी लहर तो रही ही है, शासन में भ्रष्टाचार को भी माना जा सकता है। शिक्षकों की बहाली में इतनी ज्यादा कदाचार के मामले सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट को कई हजार शिक्षकों की बहाली ही रद्द कर देनी पड़ी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री और विभागीय सचिव को महीनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। घरों से नोटों के बंडल भी मिले। इससे ममता बनर्जी की भी खूब किरकिरी हुई। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है, लेकिन क्या महिलाएं सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही असुरक्षित हैं ? हां, मीडिया की भूमिका भी बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। मीडिया ने पश्चिम बंगाल की घटनाओं को जरूर बढ़ा-चढ़ाकर प्रकाशित- प्रसारित किया। प्रशासन और पुलिस की बजाय सरकार के मुखिया को ही निशाने पर लिया। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सुशासन के बिहार में जंगलराज से ज्यादा आपराधिक वारदातें हो रही हैं, लेकिन लोकतंत्र का चौथा खंभा खामोश है। तकरीबन यही हाल कुछ और प्रदेशों का भी है।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की पराजय के पीछे विपक्ष में बिखराव और मुस्लिम मतों का विभाजन भी एक बड़ा कारण है। सबने देखा कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कैसे टीएमसी सरकार पर हमलावर थे। क्या-क्या नहीं कहा। अब हार के बाद मातमपुर्सी के लिए ममता को फोन कर रहे हैं। वह भी इसलिए कि आनेवाले लोकसभा के चुनाव में ममता कहीं अलग राह नहीं पकड़ लें। झारखंड में हेमंत सोरेन पहले से ही कांग्रेस से खफा हैं। कब पाला बदल लें, कोई नहीं कह सकता। महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे में पहले से ही एक अनार सौ बीमार की हालत है। हिमाचल में कांग्रेस आपसी कलह से कराह रही है। बिहार में विपक्ष की राज्यसभा की एक सदस्यता की हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, कांगेस और अखिलेश यादव अभी से हांफते दिखाई देते हैं। विपक्ष में बिखराव और मुस्लिम मतों के विभाजन से टीएमसी का वोट बैंक करीब 8 फीसदी गिरा। नतीजतन टीएमसी की सदस्य संख्या 215 से घटकर 81 पर पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार का निर्णायक कारण मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और केन्द्रीय सुरक्षा बलों की अभूतपूर्व तैनाती भी रहा है। राज्य में तकरीबन 91 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। हो सकता है कि इसमें मृत लोगों और दो जगहों पर मतदाता सूची में शामिल लोग भी रहे हों। लेकिन किसका नाम किस कारण से काटा गया, चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख तक कोई आंकड़ा नहीं बताया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायाधिकरण में भी सारे अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब जो लोग अपील में सही साबित हो जाएंगे, कम से कम इस चुनाव में उनकी भूमिका तो नहीं रही। अजीब हाल है। चुनाव आयोग विज्ञापन तो खूब देता है कि कोई मतदाता छूटे नहीं, लेकिन कौन मतदाता वोट डालेगा, वही तय करता है। हैरत तो यह कि चुनाव आयोग के गलत फैसले के खिलाफ अब कोई सुनवाई भी नहीं हो सकती है। सरकार ने उसे विशेषाधिकार दिया हुआ है।

जीत हमेशा ताकतवर की होती है

सनत जैन

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया है। चुनाव लड़ने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य तैयार कर लिया था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद, सभी संवैधानिक शक्तियां, टीएमएसी में अपने जासूस भेजने से लेकर वह सभी काम किया, जो चुनाव को जीतने के लिए जरूरी था। प्यार और युद्ध में सब जायज है। युद्ध और प्यार का एक ही लक्ष्य होता है, जीतना- जीतना। भाजपा के रणनीतिकार अच्छी तरीके से यह बात जानते हैं। चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। इसमें नैतिकता, नियम या कानूनों का कोई लेना-देना नहीं है। जब भगवान राम युद्ध के दौरान विभीषण और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा मारा गया, जैसी युक्ति अनैतिक लड़ाई जीतने के लिए अपना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के ऊपर जो आरोप लग रहे है, वह सब जायज हैं। यही कहा जा सकता है, जीतना ही प्रमुख लक्ष्य होता है। जो जीतता है, उसी के पास सत्ता होती है। जिसके पास सत्ता होती है, सारी शक्तियां उसी के नियंत्रण में काम करती हैं। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय सभी नौ ग्रह रावण की कैद में थे। हनुमान जी नहीं होते, उन्होंने रावण की कैद से नौ ग्रहों को नहीं छुड़ाया होता, तो भगवान राम की जीत भी संभव नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत गई है। ममता दीदी और उनकी पार्टी टीएमसी बुरी तरह से हार गई है। यही युद्ध का परिणाम है, जो जीता वही सिकंदर। इसके बाद अदालती और कोर्ट-कचहरी की लड़ाई लड़ते रहो, कुछ होने-जाने वाला नहीं है। जिसके पास सत्ता है, सारे ग्रह नक्षत्र उसी के ईशारे पर नाचेंगे। हारने वाले को यही ग्रह-नक्षत्र अपने इशारे पर नचायेंगे। पिछले कुछ वर्षों से यही होता हुआ दिख रहा है। कहा जाता है, लोकतंत्र में जनता मलिक होती है। जनता का राज होता है, पिछले एक दशक से जनता चुपचाप बैठी है। सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए पदाधिकारी सरकार के इशारे पर, जनता को अपने ईशारों पर नचा रहे हैं। भय और लालच से वशीभूत जनता चुपचाप तमाशा देख रही है। जब तक जनता में जागृति नहीं आयेगी, वह सत्ता के आगे गुलाम बनी रहेगी। जब जनता को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख जाएगी, तब जाकर वह स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करेगी। अभी तो जनता सत्ता के ऊपर निर्भर है। भाजपा जानती है, कैसे भी चुनाव जीतो और सत्ता पर काबिज हो जाओ। सत्ता की ताकत जब तक होगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पिछले कुछ समय से भारत में यही देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कह दिया, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने असंवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री ठाकरे की सरकार गिराई थी। अवैधानिक रूप से बनी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। न्यायपालिका और न्याय से आज तक कोई फैसला नहीं हो पाया। ममता बनर्जी ने कहा है, वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। राज्यपाल को अधिकार है, वह मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके नए विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी कर नई सरकार का गठन करा देंगे। नई सरकार बन जाएगी। जो भाजपा की होगी यही सत्य है। चुनाव को लेकर कोई शिकायत है, वह 45 दिन के अंदर हाईकोर्ट में याचिका दायर करे, वर्षों सुनवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जो भी फैसला करेंगे, उसका पालन होगा या नहीं यह भी भविष्य की गर्त होगा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश चुनाव को लेकर किए थे। उनका पालन हरियाणा और अन्य याचिका पिटीशन में चुनाव आयोग ने नहीं किया, अभी भी यहां से वहां लोग घूम रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का समय निकल चुका हैं। अभी तक ना तो कंट्रोल पैनल, ईवीएम मशीन तथा बीवीपेट की पर्चियां गिनी गई। तारीख पर तारीख का खेल चलता चला आ रहा है।

विकल्पहीनता से बचें, हरदम तैयार रखें 'प्लान बी'

तनाव से बचने का यही है सबसे आसान तरीका



चाहे आप छात्र हों, व्यवसायी हों या नौकरी पेशेवर, जीवन में कई बार आपको ऐसे संवादों में शामिल होना पड़ता है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यह नौकरी का इंटरव्यू हो सकता है, किसी व्यक्ति से सौदे की बातचीत हो सकती है या आपके बॉस के साथ कोई संवाद।

ऐसे कूटनीतिक किस्म के संवादों में समस्या तब आती है, जब आपके पास 'प्लान बी' न हो, यानी यदि यह अवसर हाथ से निकल जाए, तो तुरंत कोई और विकल्प न दिखे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है और उसे डर महसूस होने लगता है।

छोटे विकल्प तैयार रखें

आपके पास हमेशा कोई बड़ा या उपयुक्त विकल्प होना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार छोटे-छोटे विकल्प भी आपकी स्थिति को मजबूत बना देते हैं। अगर आप पूरी तरह किसी एक व्यक्ति या संस्था पर निर्भर हैं, तो एक छोटी-सी वैकल्पिक व्यवस्था भी आपको सहारा दे सकती है। इससे सामने वाले को संकेत मिलता है कि आप पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं हैं, और यही बात उसे अपनी शर्तों में लचीलापन दिखाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

डर को हावी न होने दें

जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, तो हम डर की वजह से जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि आप शांत रहें; हो सकता है कि सामने वाला भी किसी न किसी रूप में आप पर निर्भर हो। यदि आप केवल अपनी कमजोरियों पर ध्यान देंगे, तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है।

तुरंत 'हां' या 'ना' न कहें

इस दौरान तुरंत 'हां' या 'ना' कहना जरूरी नहीं होता। कई बार समय लेना ही सबसे प्रभावी रणनीति होती है। आप सामने वाले से सोचने के लिए समय मांग सकते हैं और इस स्थिति का शांतिपूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही, आप ऐसे छोटे-छोटे कदम भी उठा सकते हैं, जो बिना पूर्ण सहमति के ही आपकी स्थिति को मजबूत बनाएं। यह प्रक्रिया आपको धीरे-धीरे एक बेहतर और मजबूत स्थिति में पहुंचाने में मदद कर सकती है।

कई बार छोटे-छोटे विकल्प भी आपकी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं।

ऐसी स्थिति में आप शांत रहें और यह समझें कि सामने वाला भी आप पर किसी न किसी रूप में निर्भर हो सकता है।

तुरंत 'हां' या 'ना' कहने के बजाय स्थिति का विश्लेषण करें।

अपनी बात को सहज भाव से रखें, ताकि टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

बात को सहज भाव से रखें

इसमें संवाद का तरीका बेहद महत्वपूर्ण होता है। सामने वाले से धमकी भरे अंदाज में बात करने के बजाय अपनी बात को शांत और सहज तरीके से रखना बेहतर होता है, ताकि टकराव की स्थिति न बने और बातचीत नियंत्रण में रहे। आप यह कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में आपको अन्य विकल्पों पर भी विचार करना पड़ सकता है। साथ ही, अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से भी रखा जा सकता है।

दिनभर रील्स देखने से ब्रेन हो रहा बीमार

'डोपामाइन डिटॉक्स' सुधार सकता है मेंटल हेल्थ



आज के समय में अधिकतर लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं. खाली समय मिलते ही तुरंत मोबाइल फोन उठा लेते हैं. लोग घंटों रील स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं.

कई बार रील्स देखते-देखते समय का पता ही नहीं चलता है. घंटों रील देखने या फिर ऑनलाइन गेम खेलने से दिमाग स्टिमुलेशन का आदि हो जाता है. ऐसे में लोगों का काम और पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाता है. स्क्रीन टाइम की लत बचने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स करना बेहद जरूरी है.

क्या होता है डोपामाइन

डोपामाइन डिटॉक्स में इंसान को कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनानी होती है जो उसे तुरंत खुशी देती है. इसका मतलब दिमाग को रीसेट करना होता है. ताकि दिमाग फिर से सामान्य और नॉर्मल काम कर सकें. डोपामाइन डिटॉक्स का मतबल बहुत ज्यादा और गैरजरूरी उत्तेजना को कम करना है. डोपामाइन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है और ना ही खत्म करना चाहिए यह शरीर के लिए बेहद जरूरी है.

डोपामाइन ट्रिगर्स को कैसे पहचाने

डोपामाइन ट्रिगर्स वो चीजे होती है जिसे हमें तुरंत खुशी मिलती है. लेकिन लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती हैं. इंसान अपनी आदतों को देखकर डोपामाइन ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं. अगर आपकी कोई आदत आपको कंट्रोल कर रही है तो वह डोपामाइन ट्रिगर हो सकता है. जैसे बिना सोचे समझे बार-बार कोई काम करना उसके बाद पछताना समय बर्बाद करना और खुद पर कंट्रोल ना रहना.

डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें

डोपामाइन डिटॉक्स करना मुश्किल नहीं है. इसकी शुरुआत धीरे-धीरे करें. 2 से 4 घंटे तक मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं. आप चाहरें तो हफ्ते में एक दिन नो स्क्रीन डे रख सकते हैं. बार-बार नोटिफिकेशन चेक करने से बचें. जरूरत ना होतो फोन साइलेंट मोड पर रख दें. कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से दूरी बनाएं.

हर 10 में से 1 छात्र क्यों छोड़ रहा स्कूल?

नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

नीति आयोग की 2026 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. भारत में सेकेंडरी स्तर पर हर 10 में से 1 छात्र स्कूल छोड़ रहा है. जानिए किन राज्यों में ड्रॉपआउट सबसे ज्यादा है और किन राज्यों ने सुधार की मिसाल पेश की है.

स्कूल की ड्रेस, कंधे पर बैग और बड़े सपने... हर बच्चे की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है. लेकिन देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल की इस यात्रा को बीच में ही छोड़ दे रहे हैं.

नीति आयोग की मई 2026 में जारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चिंता सामने रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंडरी यानी 9वीं-10वीं स्तर पर ड्रॉपआउट रेट सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है. अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन 2024-25 में भी राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत दर्ज किया गया. यानी हर 10 में से करीब 1 छात्र स्कूल छोड़ रहा है.



किन राज्यों में हालात ज्यादा खराब?

राज्यवार आंकड़े देखें तो कई राज्यों की तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है. सबसे ज्यादा सेकेंडरी ड्रॉपआउट वेस्ट बंगाल में 20 प्रतिशत दर्ज किया गया. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और कनार्टक में 18.3 प्रतिशत, असम में 17.5 प्रतिशत और मिजोरम व मेघालय में 17.4 प्रतिशत ड्रॉपआउट दर्ज किया गया. इसके अलावा गुजरात में 16.9 प्रतिशत, एमपी में 16.8 प्रतिशत और लद्दाख में 16.2 प्रतिशत छात्रों ने सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाई छोड़ी. यह आंकड़े बताते हैं कि उच्च कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखना अभी भी बड़ी चुनौती है.

कौन से राज्य बने मिसाल?

कुछ राज्यों ने इस मामले में शानदार काम भी किया है. चंडीगढ़ में ड्रॉपआउट रेट सिर्फ 2 प्रतिशत रहा. झारखंड में यह 3.5 प्रतिशत, लक्ष्यदिप में 4.1 प्रतिशत, उत्तराखंड में 4.6 प्रतिशत और केरलम में 4.8 प्रतिशत दर्ज किया गया. ये दिखाता है कि सही नीतियों और मजबूत स्कूल सपोर्ट सिस्टम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा जा सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा योजनाओं की मजबूती और परिवारों की भागीदारी से ऐसे नतीजे संभव हुए हैं.

बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं?

रिपोर्ट बताती है कि सेकेंडरी स्तर पर आर्थिक दबाव, जल्दी नौकरी करने की मजबूरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और संस्थागत सहयोग की कमी बड़ी वजह बन रही है. हालांकि कई राज्यों ने शानदार सुधार भी दिखाया है. उडिसा में ड्रॉपआउट 49.5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत हो गया.

झारखंड में 23.2 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत, नागालैंड में 35.1 प्रतिशत से 12.1 प्रतिशत, बिहार में 25.3 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत और राजस्थान में 18.8 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई. इससे साफ है कि सुधार हो रहा है, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है.

यूपीएससी ने निकाली ग्रुप ए और बी के पदों पर भर्ती, 29 मई तक करें आवेदन

संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 45 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 29 मई 2026 शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर निकली भर्ती?

यूपीएससी की इस भर्ती में कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (कन्नड़ भाषा), कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा मंत्रालय में अनुवादक (चीनी और तिब्बती), डीआरडीओ में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II, भारतीय खान ब्यूरो में सहायक खनन अभियंता और सहायक अनुसंधान अधिकारी, तथा लद्दाख प्रशासन में लेखा अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। सबसे अधिक 29 पद डीआरडीओ में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II के लिए निर्धारित किए गए हैं।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव और विशेष कौशल भी मांगे गए हैं।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु पद अनुसार 30 वर्ष से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग, भर्ती परीक्षा (यदि आयोजित की जाए), पर्सनल इंटरव्यू और अंतिम मेरिट सूची शामिल होगी। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान स्तर 7 से 10 और अकादमिक स्तर 10 से 13A1 के तहत सैलरी दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें।

आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद की विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ लें ताकि पात्रता और अन्य शर्तों की सही जानकारी मिल सके।

यूपी में बीएड छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप अनिवार्य

पहले और दूसरे साल के लिए जारी हुआ नया शेड्यूल

बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव किया गया है. अब दो साल के बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप जरूरी होगी. नए नियम के अनुसार पहले वर्ष में 4 सप्ताह और दूसरे वर्ष में 16 सप्ताह की इंटर्नशिप करनी होगी. इस दौरान बीएड छात्र स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे और शिक्षण का अनुभव हासिल करेंगे. उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिए हैं. साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है.

सरकार ने साफ किया है कि बीएड छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी माध्यमिक स्कूलों में इंटर्नशिप दी जाएगी. अगर किसी बीएड कॉलेज के आसपास सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं होगा, तभी छात्रों को निजी स्कूलों में भेजा जाएगा. इससे प्रशिक्षुओं को बेहतर माहौल में पढ़ाने का मौका मिलेगा. साथ ही सरकारी स्कूलों



में शिक्षण व्यवस्था को भी मदद मिलेगी. अब इंटर्नशिप के लिए छात्रों को स्कूल ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी. पहले कई छात्रों को स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय पर इंटर्नशिप पूरी नहीं हो पाती थी.

इंटर्नशिप की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जिलों को इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदारी भी दी गई है. हर जिले के बीएड कॉलेज अपने छात्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजेंगे. इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक छात्रों को अलग-अलग स्कूल आवंटित करेंगे. बीएड के छात्रों को माध्यमिक स्कूलों में ही भेजा जाएगा. विभाग का मानना है कि इससे इंटर्नशिप की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी. छात्रों को सही समय पर स्कूल मिल जाएंगे और उन्हें अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी.

नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

सरकार का कहना है कि जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां बीएड छात्र पढ़ाई कराने में मदद करेंगे. इससे स्कूलों को भी राहत मिलेगी और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी. बीएड के छात्र अपने विषय के अनुसार बच्चों को पढ़ाएंगे. इससे उन्हें पढ़ाने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा. वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी फायदा होगा. उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा संस्थानों को लेकर भी बड़े बदलाव की तैयारी की है. अब सिर्फ बीएड कोर्स चलाने वाले कॉलेजों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा. यानी इन कॉलेजों में केवल बीएड ही नहीं, बल्कि दूसरे विषयों की पढ़ाई भी शुरू होगी.

संघर्ष में भी लक्ष्य कायम रहे यही आपको महान बनाता है

किताबों से जानिए, कैसे साधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं? परिस्थितियों पर उद्देश्य क्यों भारी पड़ता है?

परिस्थितियां कमजोर करें, उद्देश्य मजबूती देगा

जीवन कठिन हो जाए, तब भी अर्थ समाप्त नहीं होता। पीड़ा में धैर्य, हानि में गरिमा और संघर्ष में उद्देश्य- यही मनुष्य को महान बनाते हैं। जो जानता है कि वह क्यों जी रहा है, वह हर कैसे को सह सकता है। परिस्थितियां कमजोर कर सकती हैं, लेकिन उद्देश्य फिर से खड़ा कर देता है।

छोटे प्रयास ही स्थाई बदलाव ला सकते हैं

जीवन में बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, रोज के छोटे-छोटे सही फैसलों से आते हैं। जो काम आज आसान लगता है, वही समय के साथ आपकी दिशा तय करता है। अच्छी आदतें जब लगातार दोहराई जाती हैं, तो असाधारण परिणाम पैदा करती हैं। फर्क बड़े कदम नहीं, छोटे कदम लाते हैं।

परिणाम की चिंता छोड़ वर्तमान पर ध्यान दें

जब व्यक्ति केवल अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करना सीख लेता है, तो वह काम बेहद आसान और शांतिपूर्ण भी हो जाता है। धैर्य और निरंतर अभ्यास ही किसी भी कौशल को स्वाभाविक बना देते हैं। असली विकास जल्दी पहुंचने में नहीं, बल्कि सही तरीके से सीखने में है।

छोटी आदतें ही बड़ी सफलता लाती हैं

छोटे-छोटे निर्णय, जो रोज लिए जाते हैं, धीरे-धीरे बड़े परिणाम देते हैं। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम समय के साथ आपको सफलता की ओर ले जाता है। गलत आदतें धीरे-धीरे पीछे धकेलती हैं। सफलता किसी बड़े प्रयास का परिणाम नहीं होती, यह लगातार किए गए छोटे प्रयासों का जोड़ होती है।

'पब्लिक रिलेशन ऑफिसर' बन सवारें करियर

आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक युग में अपने उत्पादों, सेवाओं या स्वयं को प्रोमोट करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जाने लगी है। इसी कार्य को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अंजाम देते हैं। वे अपने क्लाइंट्स की इच्छा और आवश्यकताओं को समझ कर उन्हें प्रोमोट करने का जरूरी काम करते हैं।

पब्लिक रिलेशन को संवाद कला के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति के लिए इसका अर्थ उसके गुणों और उपलब्धियों को हाईलाइट करने और सही संबंध स्थापित करने से होता है, जिससे उसका करियर फल-फूल सके। वहीं एक कम्पनी के लिए इसका अर्थ मार्केट में खुद को अच्छी तरह स्थापित करने, मीडिया के साथ संबंध तथा साख कायम रखने और कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से खबरों में बने रहना होता है।

इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक पब्लिक रिलेशन प्रोफैशनल को बेहद प्रभावी और संक्षिप्त उपायों से वाकिफ होना चाहिए।

आज अत्यधिक प्रतियोगिता का युग है। जिसमें हर किसी के सामने अपने संदेश को अन्यों से अलग दिखाने की चुनौती है। और इसी कार्य में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विशेषज्ञता रखते हैं।

चुनौतियों की कोई कमी नहीं

जैसे-जैसे बिजनैस में प्रतियोगिता बढ़ रही है, पब्लिक रिलेशन अफसरों को और अधिक रचनात्मक होना पड़ रहा है। अब उनके सामने केवल लोगों के विचारों को अपने क्लाइंट्स के पक्ष में करने का ही काम नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे प्रयत्न करने पड़ते हैं, कि उनका क्लाइंट भीड़ में भी सबसे अलग दिखे। पी. आर.



एग्जीक्यूटिव अनन्या चक्रवर्ती ने अपने अनुभव सांझे करते हुए कहा, इस काम के दौरान हर दिन मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जिस भी चीज या सेवा को आप प्रोमोट करते हैं, उसके बारे में आपका ज्ञान बढ़ता है। यहां हर दिन किए जा सकते हैं। कई संस्थान थ्योरी के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए प्रैक्टिकल भी करवाते हैं।

खास कौशल

एक सफल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनने के लिए लोगों से मेल-जोल बढ़ाने की स्वभाविक रुचि होनी चाहिए। ग्रूमिंग और लैंग्वेज स्किल्स में निपुणता भी आवश्यक है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को नवीनतम बदलावों और करंट इवेंट्स से खुद को अवगत रखना होता है। उसमें सब्र की उच्च मात्रा होनी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि इस क्षेत्र में तुरंत लाभ न मिलें। कलात्मक और रचनात्मक विचार खोजने की क्षमता उन्हें विशेष रूप से लाभान्वित कर सकती है।

सम्भावनाएं

बतौर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अच्छी एड या पी. आर. एजेंसी के साथ शुरुआत करने वाले 8 हजार से 15 हजार रुपए प्रतिमाह तनख्वाह पा सकते हैं।

एक नई चुनौती है। पब्लिक रिलेशंस के कोर्स छात्र- छात्राओं को बेशक नौकरी दिलवा दें, परंतु उन्हें वास्तविक कौशल अपने प्रयत्नों और गलतियों से सीखने को मिलते हैं।

योग्यता

किसी होटल में बतौर पी. आर. काम करना सीखने का एक अच्छा जरिया है, जिसके दौरान अच्छी आय भी हासिल की जा सकती है।

परंतु इस क्षेत्र में वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब व्यक्ति अनुभव हासिल करे और अपने अच्छे- खासे कांटेक्ट बना कर व्यक्तिगत तौर पर कार्य शुरू करे।

विभिन्न संस्थान, विशेष रूप से पब्लिक रिलेशंस में अथवा जर्नलिज्म के कोर्स में, इसे एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं। किसी भी विषय में ग्रैजुएशन के बाद ये कोर्स

प्रमुख संस्थान

* भारतीय विद्या भवन, दिल्ली। * इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिल्ली।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट्टी में मिल गए: योगी



लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वाराणसी में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव को संबोधित करते हुए काशी और सोमनाथ मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया और इन्हें भारत की सभ्यतागत चेतना की शाश्वत लौ के स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में दोनों मंदिरों पर अनेक हमले हुए हैं और सनातन धर्म को मिटाने के प्रयास असफल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय आत्मसम्मान के पुनरुत्थान का आह्वान है। सोमनाथ संकल्प महोत्सव इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि वे यह समझने में विफल रहे कि सनातन धर्म केवल मंदिरों की दीवारों के भीतर ही नहीं बसता, बल्कि भारत की चेतना में भी बसता है। और भारत की चेतना आत्मा को शाश्वत और अमर मानती है। जिन्होंने सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किया, वे स्वयं धूल में मिल गए हैं।

ओवैसी और लादेन में कोई अंतर नहीं : नितेश राणे



मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नितेश राणे ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पर तीखा हमला बोला है। यह हमला पार्षद मतीन मजीद पटेल पर नासिक टीसीएस मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को पनाह देने के आरोप के बाद किया गया है। राणे के इस बयान ने एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एआईएमआईएम को आतंकवादी संगठन करार दिया और इसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और ओसामा बिन लादेन के बीच विवादास्पद तुलना की। उन्होंने दावा किया कि ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा द्वारा किए जाने वाले काम को अब ओवैसी एआईएमआईएम के माध्यम से दोहरा रहे हैं। ओसामा बिन लादेन और असदुद्दीन ओवैसी में कोई अंतर नहीं है। ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के माध्यम से जो काम करता था, वही काम अब असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के माध्यम से कर रहे हैं।

एआईएडीएमके में चुनावी हार के बाद बगावत



चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने एआईएडीएमके के भीतर एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पार्टी की करारी हार के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ नेता सी.वी. शनमुगम के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की है। हालांकि, सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्टी के कुछ तबकों से बढ़ते दबाव के बावजूद ईपीएस इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं हैं। एआईएडीएमके के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के वरिष्ठ नेता सी.वी. शनमुगम के साथ जुड़े विधायकों और कई पूर्व मंत्रियों ने ईपीएस को साफ़ कह दिया है कि लगातार चार चुनावी हार के बाद वे अब उनकी लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। 23 अप्रैल को हुए चुनावों में एआईएडीएमके के 293 सीटों में से सिर्फ़ 47 सीटें ही जीत पाई थी।

केरल में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार



तिरुवनंतपुरम। केरल में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बावजूद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के शनिवार को नई दिल्ली में दावेदारों के साथ बैठक किए जाने के दो दिन बाद भी पार्टी नेतृत्व किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला, केसी वेणुगोपाल और विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशान प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इन तीनों नेताओं के साथ पार्टी हाईकमान ने शनिवार को अलग-अलग चर्चा की थी। बैठक में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ और केरल प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी भी मौजूद थीं। सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी अध्यक्ष खरगे की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि हाईकमान राज्य में पिछले सप्ताह देखने को मिले विरोध प्रदर्शनों और पोस्टर वार के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं।

हिमंता बिस्वा सरमा आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ



गुवाहाटी। असम के भावी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार रात गुवाहाटी पहुंचेंगे। आज सुबह (11 मई) 11 बजे असम की नई सरकार शपथ लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और एनडीए-शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। हमारे पार्टी के बूथ-स्तर के कार्यकर्ताओं सहित कई लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भावी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा- शपथ लेने के बाद, हम पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। हमारे घोषणापत्र को लागू करना ही हमारा लक्ष्य होगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान का दौरा किया।

मोदी की अपील के बाद सरकार की सफाई

देश में सभी तरह के ईंधन और ऊर्जा का पर्याप्त भंडार



दिल्ली प्रदेश जदयू ने पेट्रोल-डीजल बचाने की मोदी की अपील का किया स्वागत

नयी दिल्ली। दिल्ली प्रदेश जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने देश हित में पेट्रोल-डीजल की बचत करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का स्वागत किया है।जदयू के प्रदेश महासचिव सर्वेश कश्यप ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए वैश्विक स्तर पर उत्पन्न पेट्रोल-डीजल संकट के बीच श्री मोदी द्वारा देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत, वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल माध्यमों के अधिक उपयोग की अपील का स्वागत किया और इसे इसे दूरदर्शी तथा राष्ट्रहित में की गयी अपील बताया।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर लोगों से ईंधन बचाने, सोना न खरीदने और विदेश यात्रा न करने की अपील के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अपील देश पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए की गयी है और देश में कच्चा तेल, रसोई गैस या अन्य किसी भी तरह के ईंधन की कमी नहीं हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सुश्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि इस कठिन समय में वे ऊर्जा संरक्षण के सभी कदम उठायें और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढायें जिससे कि देश पर निरंतर बढ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में कच्चे तेल सहित सभी तरह के ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और किसी भी पेट्रोल पंप या गैस वितरण कंपनी से किसी भी तरह की कमी की जानकारी नहीं मिली है।उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना दुनिया का सबसे बड़ा व्यवधान है। इस रास्ते से दुनिया की 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति की जाती है जिससे भारत भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए अनेक प्रभावशाली कदम उठाये हैं और घरेलु उपभोक्ता को गैस आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि भारत में 40 प्रतिशत कच्चा तेल और 90 प्रतिशत एलपीजी आयात की जाती है। सरकार ने सभी रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन बढाने का निर्देश दिया हुआ है।

सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से एलपीजी और पीएनजी को बढावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि कंपनी महंगी ऊर्जा खरीद कर देश में सस्ती बेच रही है जिससे उनपर आर्थिक दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आग्रह को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण करते हुए कैसे आर्थिक बोझ को कम किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे हड़बड़ी में खरीद न करें। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी किसी भी क्षेत्र के लिए किसी तरह के पैकेज की योजना नहीं है।अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसे उसी भावना में समझा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के कहने का मतलब है कि कठिन समय में उपलब्ध संसाधनों का उचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसे इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि देश में इन चीजों की बहुत कमी है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में अभी भी भारतीय ध्वज वाले 13 जहाज हैं और उन्हें सुरक्षित लाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार इन जहाजों के नियमित संपर्क में है।

उर्वरक मंत्रालय की ओर से कहा गया कि देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है।

बंगलादेश सीमा पर कंटीले तार लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करेगी सरकार



कोलकाता>पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक, सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों की घोषणा करते हुए भारत-बंगलादेश सीमा पर कंटीले तार लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।राज्य सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिमंडल बैठक के बाद कहा, आज हमारी पहली कैबिनेट बैठक में हमने सीमा पर कंटीले तार लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अगले 45 दिनों के भीतर यह भूमि गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गयी है कि पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो। इसके बाद बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा करेगी और अवैध घुसपैठ की समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा।

राज्य की बंगलादेश के साथ साझा 2216.7 किलोमीटर लंबी सीमा का बड़ा हिस्सा अब भी बाड़रहित है और भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा अवसंरचना निर्माण के लिए बीएसएफ को भूमि उपलब्ध कराना हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख मुद्दों में शामिल था। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि वह जानबूझकर बीएसएफ को भूमि उपलब्ध नहीं करा रही थी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सक्रिय रूप से सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों का समर्थन कर रही थी, जिन्हें बाद में नौ सीमावर्ती जिलों में वोट बैंक में बदला गया।

श्री अधिकारी ने बेरोजगारी की समस्या कम करने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने राज्य में सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देगी तथा राज्य को केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से अधिक निकटता से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। सरकार बनाने के लिए जनता ने हम पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।मुख्यमंत्री की ओर से की गयी प्रमुख घोषणाओं में राज्य का औपचारिक रूप से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ना भी शामिल है। उन्होंने कहा, हमने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क कर सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करें। इस दौरान उनके साथ मंत्री दिलीप घोष, निशित प्रामाणिक, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया और क्षुदिराम टुडू उपस्थित थे।

आयुष्मान भारत योजना के अलावा राज्य में जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फसल बीमा योजना और उजाला योजना जैसी केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं भी लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की भी घोषणा की। इसके तहत आईएएस अधिकारियों को केंद्रीकृत प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ने की योजना बनायी गयी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य की प्रक्रियाओं को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने का निर्णय लिया।श्री अधिकारी ने पूर्ववर्ती सरकार पर गृह मंत्रालय के जनगणना संबंधी निर्देशों के क्रियान्वयन में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आज हमने जनगणना प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किया है। 11 महीने की देरी के बाद अब यह लंबित प्रक्रिया शुरू की जा रही है।उन्होंने आरोप लगाया, जनगणना प्रक्रिया को जानबूझकर रोका गया था। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री की परिसीमन प्रक्रिया और महिलाओं, विशेषकर माताओं एवं बहनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की पहल को बाधित करना था। इसकी जांच के लिए तथ्य अन्वेषण समिति गठित की जाएगी।मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ी सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, हम किसी भी गैर-भारतीय अथवा बेईमान व्यक्ति को पिछली व्यवस्था की खामियों का लाभ उठाकर इन योजनाओं का फायदा नहीं लेने देंगे। सब कुछ पारदर्शी होगा।

खेल
प्रमुख समाचार

पाकिस्तान-बांग्लादेश से सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान



सिडनी। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बाहर होते ही ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और मई-जून 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की है। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए खेल रहे मिचेल मार्श दोनों ही फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।

पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को आराम दिया गया है। वनडे टीम में बिली स्टैनलेक और राइली मेरेडिथ की वापसी हुई है। ओली पीक, लियाम स्कॉट और जोएल डेविस को पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। पीक को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है, जबकि स्कॉट को बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई है। जोएल डेविस बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ टी20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे।

आईपीएल 2026 में खेल रहे ट्रेविस हेड, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस और जेवियर बार्टलेट बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में पीक, स्टैनलेक, मेरेडिथ और मैट शॉर्ट की जगह लेंगे। वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले चुके ग्लेन मैक्सवेल को टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया है।

पीक, स्कॉट और डेविस को घरेलू प्रदर्शन में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। स्कॉट को 2025/26 में शेफील्ड शील्ड प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था, जबकि डेविस 2025/26 बिग बैश लीग में सबसे अहम खिलाड़ी रहे थे। ओली पीक अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रहे थे, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल किया गया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1313 अंक लुढ़का निफ्टी 23,800 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार आज तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी50 और सेंसेक्स दोनों में बड़ी कमजोरी देखने को मिली। बाजार पर सबसे ज्यादा असर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी सेक्टर के शेयरों की गिरावट का रहा। निफ्टी50 सोमवार को 360.30 अंक यानी 1.49% गिरकर 23,815.85 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1,312.91 अंक यानी 1.70% टूटकर 76,015.28 पर बंद हुआ। निफ्टी50 में टाइटन कंपनी, इंटरग्लोब एविएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़े नुकसान वाले शेयर रहे। वहीं, बड़े बाजार के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी दबाव रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.05% गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.13% नीचे बंद हुआ। सेक्टरों की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में करीब 4% की भारी गिरावट दर्ज की गई।

ऊर्जा और डिजिटल सुरक्षा तय करेंगे भविष्य की वैश्विक ताकत

नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडानी ने भारत से कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान करते हुए कहा है कि आने वाले समय में ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना ही वैश्विक शक्ति संतुलन तय करेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक बिजनेस समिट 2026 को संबोधित करते हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अब डेटा, सेमीकंडक्टर तथा क्लाउड तकनीक रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज वैश्वीकरण का पुराना मॉडल कमजोर पड़ रहा है और दुनिया प्रतिस्पर्धी गुटों में बंटती जा रही है। ऐसे माहौल में भारत को एआई को केवल सॉफ्टवेयर तकनीक नहीं बल्कि ऊर्जा, डेटा सेंटर, चिप निर्माण, नेटवर्क, कंप्यूटिंग क्षमता और प्रतिभा विकास से जुड़ी संपूर्ण रणनीतिक अवसंरचना के रूप में देखना होगा।

मोदी की अपील से 3 लाख करोड़ के गोल्ड कारोबार पर संकट

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने देश के ज्वेलरी कारोबार में हलचल बढ़ा दी है। हैदराबाद में रविवार को आयोजित एक रैली में पीएम मोदी ने नागरिकों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाने का आग्रह किया। भारत में हर साल लगभग 40 से 50 लाख शादियां होती हैं और शादी के गहनों का कारोबार अरबों रुपए का माना जाता है। आमतौर पर एक शादी में 50 से 100 ग्राम तक सोने के आभूषण खरीदे जाते हैं। यही वजह है कि देश में होने वाली कुल सोने की बिक्री का करीब 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा वेडिंग सीजन में होता है। उद्योग से जुड़े संगठनों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में केवल वेडिंग ज्वेलरी सेगमेंट में ही 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक का कारोबार हो सकता है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील से ज्वेलर्स को बिक्री में भारी गिरावट की आशंका सताने लगी है।

महाराष्ट्र में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लगाएगी नया संयंत्र

नई दिल्ली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर महाराष्ट्र में एक नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी जहां 2029 की पहली छमाही में उत्पादन शुरू किया जाएगा। कंपनी ने इस संयंत्र में निवेश की राशि का खुलासा नहीं किया। हालांकि, जापान की मीडिया की खबरों के अनुसार मूल कंपनी टोयोटा मोटर भारत में क्षमता विस्तार के लिए महाराष्ट्र में करीब 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। वाहन विनिर्माता कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि नया वाहन विनिर्माण संयंत्र महाराष्ट्र के बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, नए संयंत्र से उत्पादन 2029 की पहली छमाही में शुरू करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में टोयोटा के कारोबार की बुनियाद को और मजबूत करना है।

तेल की लकीरें, अबूधाबी-अरब और रेत पर खिंची रेखाएं

अंशुमान तिवारी

28 अप्रैल, 2026। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के ऊर्जा मंत्री सुहैल मोहम्मद अल-मजरूई प्रेस के सामने आए। शांत आवाज। सधे हुए शब्द। यूएई ने एक मई, 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैसला किया है। सवाल पूछा गया, क्या आपने सऊदी अरब को पहले बताया? मजरूई बोले, 'हमने यह मुद्दा किसी देश के साथ नहीं उठाया।' 64 साल पहले बगदाद के उस कमरे में, जो दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर गठजोड़ बना था, उसकी एक बड़ी दीवार ढह गई। गिरा भी वह, जिसे सऊदी अरब का सबसे भरोसेमंद साझीदार माना जाता था।

1960 में तेल की दुनिया को दो नाम मालूम थे-जकी यमानी और अल्फांसो पेरेज अलफोन्जो। एक सऊदी, दूसरा वेनेजुएला का। दोनों के मन में एक ही जिज्ञासा थी कि तेल हमारा, तो मुनाफा हमारा क्यों नहीं? दोनों ने मिलकर अमेरिकी-यूरोपीय कंपनियों से अपना तेल उद्योग वापस ले लिया। और बना दिया दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन, यानी ओपेक। इसने तेल बाजार पर राज किया। मगर अब दुनिया का यह सबसे मजबूत संगठन टूट गया। क्या रेत के नीचे दरार थी? एक रंजिश, जो सत्तर साल से सुलग रही थी, और अब फट पड़ी है!

आइए, टाइम मशीन गुर्रा रही है। डायल पर दिख रही है तारीख 26 दिसंबर, 1915। तारुत, फारस की खाड़ी। पहले विश्वयुद्ध का धुआं अभी थमा नहीं है। ओटोमन साम्राज्य ढह रहा है। ब्रिटेन को अरब के रेगिस्तान में एक भरोसेमंद दोस्त चाहिए। वह सामने हैं इब्न सऊद, नज्द के अमीर। अरब की रेत से उठा एक जंगजू, जिसने 1902 में महज 40



लोगों के साथ रियाद पर कब्जा किया था। दूसरी तरफ हैं ब्रिटिश डिप्लोमेट सर पर्सी कॉक्स। ट्रीटी ऑफ डॉरिन पर दस्तखत। ब्रिटेन ने इब्न सऊद को मान्यता दी है। इब्न सऊद बदले में देते हैं-ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटेन का साथ और एक वादा कि वह कुवैत, कतर और संधि राज्यों पर हमला नहीं करेंगे। यही संधि राज्य आगे चलकर यूएई बनेंगे। खाड़ी के किनारे सात छोटी-छोटी रियासतें हैं। अबूधाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल-कैवैन, फुजैराह, रास अल-खैमाह। 1820 से ब्रिटेन ने इनके साथ एक के बाद एक संधियां कीं, जिसके तहत ये रियासतें किसी भी विदेशी शक्ति से बिना ब्रिटेन की इजाजत के बात नहीं कर सकतीं। बदले में ब्रिटेन इनकी रक्षा करता है। डॉरिन की संधि में इन राज्यों की हिफाजत करने का वादा ब्रिटेन ने किया है, पर सऊदी उन्हीं पर नजरें गड़ाए हुए है। ब्रिटेन ने एक ही हाथ से दो दोस्त बनाए, जबकि दोनों एक-दूसरे के दुश्मन थे। यह रेत पर खिंची पहली लकीर है। आगे की हर दरार की जड़ यहीं है।

31 अगस्त, 1952। टाइम मशीन अबूधाबी की सरहद पर बुरैमी के पास उतर रही है। वह देखिए-धूल का बादल। सऊदी अमीर तुर्की बिन अब्दुल्लाह अल-उतैशान की अगुवाई में सऊदी गार्ड अबूधाबी की सरहद पार करके हमासा गांव पर कब्जा कर रहे हैं। सऊदी ने कहा, यह जमीन उसी की है। पर, असल वजह कुछ और है। तेल कंपनी अरामको को पता लगा है कि बुरैमी के नीचे तेल हो सकता है। तेल की गंध ने लालच बढ़ाया, सरहदें खींचीं, बारूद बाद में आया। अबूधाबी में उस शेख को देखिए। वह हैं शेख जायद बिन सुल्तान अल अहयान। अल-ऐन के शासक। यही आगे चलकर यूएई के संस्थापक बनेंगे। यह 1954 है। जिनेवा में मध्यस्थता कराने वाला अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल टूट गया है। सुर्खियों में है कि सऊदी अरब ने ट्रिब्यूनल के अरब सदस्य को 'खरीद' लिया है। पांच अक्तूबर, 1955। बुरैमी में जंग को दूर से देखिए। ब्रिटेन ने अबूधाबी का साथ दिया है। सऊदी अमीर बिन नामी को गोली लगी है। यह जनवरी 1968 है। ब्रिटेन टूट चुका है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद साम्राज्य का बोझ उठाना असंभव हो गया है। पाउंड की कीमत गिरी है। प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन घोषणा कर रहे हैं कि ब्रिटेन अरब इलाकों से अपनी सेनाएं 1971 तक वापस बुला लेगा।

सुशासन तिहार 2026 ग्रामीणों के लिए साबित हुआ प्रभावी पहल

उम्मीद की नई किरण बना सुशासन तिहार



रायपुर। सुशासन तिहार 2026 को ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रभावी और उपयोगी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस अभियान के जरिए सरकार ने सीधे गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, जिससे ग्रामीणों में सकारात्मक माहौल बना है। कार्यक्रम के दौरान कई गांवों में लोगों की शिकायतें मौके पर ही सुनी गईं और कई मामलों का तुरंत निपटारा किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की पहल से प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम हुई है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से मिलने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर ग्रामीणों में संतोष देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि सरकार की यह पहल जमीन स्तर पर बदलाव लाने में मददगार साबित हो रही है। इस अभियान ने ग्रामीण विकास और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया है।

मौके पर ही निराकरण राज्य शासन का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि गांव स्तर पर ही समाधान उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित कर आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहें।

शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। यहां आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा एवं उज्ज्वला योजना सहित अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभान्वित भी किया गया।

सुशासन से समय और धन की बचत सरकार का मूल मंत्र अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। सुशासन तिहार के जरिए हम जनता के द्वार तक पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत हो रही है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शेष आवेदनों का निराकरण एक सप्ताह के भीतर संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यदि कोई आवेदक किसी योजना हेतु पात्र नहीं पाया जाता, तो उसे कारण सहित स्पष्ट जानकारी दी जाए ताकि कोई भ्रम न रहे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई ।कोमल साहू को एक घंटे के भीतर लर्निंग लाइसेंस मिला कोमल साहू ने बताया कि उन्होंने हाल ही में नई गाड़ी खरीदी है, जिसके लिए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता थी। समाधान शिविर में पहुंचकर उन्होंने आवेदन किया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें शीघ्र ही लर्निंग लाइसेंस मिल गया। उन्होंने कहा कि शिविर में बिना किसी परेशानी के त्वरित सेवा मिलने से उन्हें काफी सुविधा हुई।

औद्योगिक विकास को मिलेगी गतिः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न



रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय (महानदी भवन) में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के केंद्र में रही प्रमुख परियोजनाएं में बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का विकास, नवा रायपुर में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, धमतरी (छाती) एवं बलौदाबाजार (चंदेरी) मे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास के अलावा भिलाई में कमर्शियल टॉवर और फ्लेटेड फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है।

निवेश बढ़ाने और नियमों के सरलीकरण पर जोर मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ करने और राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को बाधा-मुक्त बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही, इंडस्ट्रियल पार्क के आवंटन नियमों में सुधार और उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा हुई।

नगरीय प्रशासन विभाग की नई सचिव पहुंचीं इंद्रावती भवन



रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की नई सचिव शंगीता आर. ने आज सवेरे नवा रायपुर में इंद्रावती भवन पहुंचकर विभागीय संचालनालय और सूडा कार्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने इस दौरान सभी कार्यालयीन कक्षों में जाकर अधिकारियों-कर्मचारियों से बातचीत कर उन्हें कार्यस्थल पर समयबध्द् उपस्थिति, प्रशासनिक कुशलता और तन्मयता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभागीय तथा सूडा के अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नगरीय प्रशासन विभाग की नवपदस्थ सचिव शंगीता आर. ने इंद्रावती भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों और योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने नगरीय निकायों के कार्यों, योजनाओं, अधोसंरचना विकास, स्वच्छता, जलप्रदाय, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन तथा अन्य शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सर्वजन हिताय के मूल-मंत्र को ध्यानन में रखते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए समयबध्द तरीके से कार्य करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित किया।सचिव शंगीता आर. ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी कार्यों और परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सीटीईटी के लिए आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 10 जून

CTET
Central Teacher Eligibility Test

रायपुर। सोमवार को सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) ने सितंबर 26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी अभ्यार्थी आवेदन भरना चाहते हैं वो आज से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए यानी आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 जून है। परीक्षा 6 सितंबर को होगी। अभ्यार्थी इस बार अपने पसंद का शहर नहीं चुन पाएंगे। इस बार परीक्षा के लिए शहर रेंडम बेसिस पर दिया जाएगा। आवदेन पोर्टल पर अभ्यार्थियों को अपने लिए परीक्षा का शहर चुनने का कोई विकल्प नहीं मिलेगा। शहर बदलने का भी कोई अनुरोध नहीं स्वीकार होगा।

आवेदन भरने की प्रक्रिया 11 मई 2026 से शुरू हुई है और इसकी अंतिम तिथि 10 जून 2026 होगी। इसके अलावा परीक्षा 6 सितंबर को होगी और अगर अभ्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तो फिर एक दिन पहले यानी 5 सितंबर को भी आयोजित हो सकती है। बता दें कि आवेदन भरने के बाद उसमें सुधार करने के लिए 15 से लेकर 18 जून तक का समय दिया गया है। परीक्षा के रिजल्ट अक्टूबर के अंत तक आ सकते हैं। आवेदन सिर्फ सीटीईटी की वेबसाइट https://ctet.nic.in , CBSE https://www.cbse.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होगा पत्रकारिता मार्तण्ड उत्सव



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में रायपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 30 मई को आयोजित पत्रकारिता मार्तण्ड उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री साय ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारिता मार्तण्ड उत्सव के पोस्टर का विमोचन भी किया।

प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने बताया कि यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा, लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका तथा पत्रकारिता के योगदान को सम्मानित और स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने जानकारी दी कि कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों, मीडिया विशेषज्ञों, साहित्यकारों तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों की सहभागिता रहेगी। आयोजन के अंतर्गत पत्रकार सम्मान, विचार गोष्ठी, विशेष व्याख्यान एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास, प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष गौरव शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री परिस्थितियों से डरकर सरेंड कर रहे है :बैज



रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के नागरिकों से सोना नहीं खरीदने तथा पेट्रोल, डीजल बचाने की अपील पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्थितियों के सामने सरेंड कर रहे है तथा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे है। प्रधानमंत्री अपनी विफलता को देशभक्ति से जोड़कर जनता को बेवकूफ बना रहे है। यदि देश में पेट्रोलियम, डीजल का संकट है तो उसके पीछे मोदी सरकार की विफल नीतियां है। मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति को भारत की पारंपरिक विदेश नीति को अपनाये होते रूस जैसे भारत के पारंपरिक मित्र के साथ खड़े होते, अमेरिका-ईरान युद्ध में भारत का झुकाव अनावश्यक रूप से अमरिका के साथ नहीं होता तो देश के सामने पेट्रोलियम की कमी समस्या नहीं आती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी की अपील के बाद भाजपाई, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, साइकिल से चले डीजल-पेट्रोल बचाये। प्रधानमंत्री की सलाह पर अमल पहले उनके दल के लोगों को करना चाहिए, उसके बाद आम जनता से अपेक्षा करे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोना नहीं खरीदने का आह्वान कर यह साफ किया कि देश की विदेशी मुद्रा का भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है।

सरकार पर्याप्त उर्वरक की व्यवस्था नहीं कर पाई है : शुक्ला



रायपुर। कांग्रेस ने कहा कि उर्वरको की उपलब्धता पर सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सभी समाचार पत्र खबरे छप रहे कि खरीफ सीजन के पहले उर्वरकों की कमी होने वाली है, लेकिन सरकार इस विषय पर कोई भी ठोस बात किसानों के सामने नहीं रख रही है। इसमें किसान परेशान है। पिछले वर्ष उर्वरकों की कमी को झेल चुके किसान सरकार के मौन के कारण विचलित हो रहे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कुल 2058 सहकारी समितियां है, जिनकी भंडारण क्षमता 4,84,665 मीट्रिक टन है। वहीं खरीफ सीजन के लिये कुल लक्ष्य 15 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले अब तक लगभग 51000 मीट्रिक टन उर्वरक का ही भंडारण हो सका है, जो लक्ष्य का मात्र 35.95 प्रतिशत है। यह स्थिति बताती है कि यदि आपूर्ति की गति नहीं बढ़ी तो खरीफ सीजन में संकट गहरा सकता है। प्रदेश में डीएपी का भंडारण लक्ष्य 2,25,650 मीट्रिक टन तय किया गया है। जबकि अब तक सिर्फ 25 प्रतिशत भंडारण हो पाया है। इनमें बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कई जिले इस मामले में सबसे पीछे है।

डीएड अभ्यर्थी आंदोलन पर सरकार मौन क्योंः ठाकुर



रायपुर। डीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग का समर्थन करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डीएड अभ्यर्थियों सहायक शिक्षकों की 2300 से अधिक पद नियुक्ति की मांग को लेकर माना तूता धरना स्थल पर भरी गर्मी में 137 दिनों से आंदोलन पर है। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के कारण अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मानसिक तनाव एवं खुले में रात-दिन आंदोलन करने के कारण मौसम का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आंदोलनकारियों की तबियत खराब हो रही है। काजल तिर्की, के बाद शैलेन्द्र साहू की तबियत खराब हुई, ऑपरेशन हुआ है। आंदोलकारियों ने सरकार तक अपनी बात पहुँचाने जल सत्याग्रह, अंगार में चलना, दण्डत्व यात्रा, मुख्यमंत्री निवास घेराव सहित नाना प्रकार के प्रदर्शन कर चुके है लेकिन सरकार उनकी मांगों पर आखिर संवेदनशीलता से विचार क्यों नहीं कर रही है? जबकि सहायक शिक्षकों के 2300 पदों पर डीएड अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का कोर्ट का भी आदेश है। सरकार आखिर उनकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों की 60 हजार से अधिक पद रिक्त है। भाजपा ने युवाओं को वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरी और 57 हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी।

सरकार उद्योग को राहत देने ठोस प्रयास करें: वर्मा



रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की लापरवाही के कारण गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में उद्योगों के सामने संकट आ गया है। छत्तीसगढ़ में लौह उद्योगों के लिये बड़ी संख्या में कमर्शियल एलपीजी की आवश्यकता होती है ताकि लोहे को काटा जा सके। पिछले 2 महीने से उद्योगों को कार्मिशियल सिलेंडर उद्योगों को नही मिल रहा है। उद्योगों में तालाबंदी की नौबत आ गई है। हजारो श्रमिक का रोजगार छीन रहा है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा अभी तक उद्योगों को राहत देने कोई ठोस प्रयास नही किया गया। न उद्योग मंत्री न ही मुख्यमंत्री के इस मामले में बयान नही आया है। गैस की कमी के कारण उद्योगों के सामने, तथा मजदूरों के सामने अपने अतिस्तत्व को बचाने की गंभीर स्थिति पैदा हुयी है।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार तत्काल कार्मिशयल गैस सिलेण्डर उपल्बध कराये इस दिशा में केन्द्र सरकार से बात किया जाना चाहिये क्योकि न सिर्फ उद्योगों को जिंदा रखने का मामला है बल्कि इन उद्योगो से जुड़े हजारो मजदूरों के रोजी रोटी का मामला है।

20 मई को दवा दुकानें बंद एसोसिएशन का फैसला

रायपुर। जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 20 मई को प्रस्तावित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद की सूचना दी है। औषधि व्यापार एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर हस्तक्षेप एवं अनुशंसा करने का अनुरोध किया। औषधि विभाग प्रदेश भर में के पखवाड़े भर का जांच अभियान चला रहा है। इसे लेकर भी दवा दुकानदारों ने नाराजगी जताई है। संघ के अध्यक्ष विनय कृपलानी एवं सचिव संजय रावत ने बताया कि यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर किया जा रहा है, जो देशभर के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट्स एवं वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है। संघ ने बताया कि लंबे समय से लंबित प्रमुख मांगों में अवैध ई-फार्मेसी संचालन पर रोक, बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा प्रिडेटोरी प्राइसिंग पर नियंत्रण तथा अधिसूचना G.S.R. 220(E) 26 मार्च 20 एवं ल.स.क्र 817(E) 28 अगस्त 18 की वापसी शामिल हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अनियंत्रित ई-फार्मेसी संचालन एवं अत्यधिक छूट आधारित व्यापार व्यवस्था से पारंपरिक औषधि वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है। इससे छोटे एवं मध्यम दवा विक्रेताओं के समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री, एंटीबायोटिक्स एवं आदत बनाने वाली दवाओं की आसान उपलब्धता, नकली प्रिस्क्रिप्शन तथा गलत भंडारण जैसी समस्याएं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं।

नगर निगम रायपुर में सुशासन तिहार

जोन-3 में पहला जन समस्या निवारण शिविर



रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आज सुशासन तिहार का पहला शिविर नगर निगम जोन-3 अंतर्गत बीटीआई मैदान के पास सिंधु भवन में आयोजित किया गया। वार्ड क्रमांक 12, 29, 30, 31, 33 एवं 48 क्षेत्र के निवासियों से आवेदन लिए गए। कार्यक्रम के दौरान नगर निवेश विभाग में 03, स्वास्थ्य विभाग में 05, बिजली विभाग में 03, खाद्य विभाग द्वारा 5 राशन कार्ड, पुलिस विभाग में 02, परिवहन में 01 तत्काल आवेदन का निराकरण किया गया। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन पर सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों की समस्याओं का एक ही प्लैटफॉर्म में समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन मांगो, शिकायतों का समाधान रायपुर नगर निगम के माध्यम से नहीं हो सकता उनका समाधान करने राज्य शासन के निर्देश पर सुशासन तिहार शिविर लगाया जा रहा है। जहां प्राप्त सभी शिकायतों का अगले एक माह के भीतर राज्य शासन के निर्देश पर त्वरित समाधान किया जायेगा। महापौर ने जोन 3 कमिश्नर एवं जोन के अधिकारी जोन क्षेत्र में अवैध कब्जों की शिकायतो पर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा जल संकट की अनेक शिकायतो गर्मी में आ रही है। जिनका जोन 3 क्षेत्र हेतु शीघ्र खम्हारडीह पानी टंकी का निर्माण प्रारंभ होने समाधान हो जाएगा।

रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी योजनाएं आमजनों तक पहुंचे और उनकी समस्या का समाधान भी हो। इसके लिए जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शिविर में आप सभी आम नागरिक इस शिविर में अपना आयुषमान कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, श्रम कार्ड इत्यादि का लाभ उठाएं। सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 पात्र हितग्राहियों को आवेदन देते हुए मकान निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया एवं 5 नागरिको को तत्काल राशन कार्ड बनाकर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सुशासन तिहार में आमजनों की समस्याएं व मांगे सुनकर उनका त्वरित समाधान किया जायेगा।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नागरिकों को सुविधा देने उनके सुशासन तिहार अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है।

बिरगांव में पानी की किल्लत पर आप पार्टी ने निगम ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन



रायपुर। राजधानी रायपुर सहित बिरगांव नगर निगम एरिया में उत्पन्न भीषण पेयजल संकट ने आम नागरिकों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। समुचित पेयजल आपूर्ती की मांग को लेकर प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ़ के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने बताया कि बिरगांव के कई इलाकों में लोग पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं। अनेक इलाकों में लगातार जल स्तर गिरने के कारण बोर सूख गया है और लोग परेशान हैं। लोगों ने निगम प्रशासन से पानी टेंकरों की मांग की लेकिन निगम कई जगह पानी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। नगर निगम आम जनता के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति करने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। इसी को लेकर आज 11 मई 2026 को आम आदमी पार्टी द्वारा बिरगांव के नगर निगम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया गया । आज के प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी की ओर से अनुषा जोसेफ, शिव शर्मा कलावती मार्को, इमरान खान,देवेंद्र गुप्ता,विकास दास मानिकपुरी, विजय देवांगन, बलवंत सिंह,नूतेश शर्मा, प्रिया शर्मा, तीरथ राम मिश्रा, नितेश कुमार दुबे, मुदलियार सहित अनेक साथी शामिल रहे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.